राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 37 ▪ अंक 3 ▪ अगस्त 2016 ▪ ₹10 ▪ पृष्ठ 36

आतंक से समझौता नहीं

पदक कम, दिल ज्यादा जीते

वैदिक मूल्यों पर आधारित आस्था का माहौल

जी.एस.टी. एक बेहतर कदम

आत्महत्या की प्रवृत्ति पर आत्ममंथन की जरूरत

रचनात्मकता

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर
से मुलाकर करते अभाविप के प्रतिनिधिगण

दिल्ली प्रांत की मीडिया-कार्यशाला, 16-17 जुलाई, 2016 में विचार रखते अतिथिगण

पुस्तक-वितरण समारोह, असम

विशाल छात्रा सम्मेलन, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति

शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका

वर्ष 37, अंक 3
अगस्त, 2016

संपादक-मण्डल :
आशुतोष
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
छात्रशक्ति भवन, 26 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली-110002; फोन : 011-23216298
वेबसाइट : www.abvp.org

chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/chhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली-110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ.आई.ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रित।

इस अंक में...

पृष्ठांक

4 संपादकीय

5 "आतंक से समझौता नहीं करेगा भारत"

11 अभाविप का विधानसभा घेराव, पुलिस ने भाँजीं लाठियाँ

12 आई फील सेफ

13 रियो ओलंपिक : पदक कम, दिल ज्यादा जीते

16 जी.एस.टी. : एक बेहतर कदम

20 आत्महत्या की प्रवृत्ति पर आत्ममंथन की जरूरत

22 प्रमुख स्वामी ने रचा वैदिक मूल्यों पर आधारित आस्था का माहौल

27 छात्रसंघ-चुनाव : धनबल, बाहुबल और सत्ताबल की राजनीति

30 प्राचीन धरोहरों का संरक्षण ही विकासार्थ विद्यार्थी का उद्देश्य : सविन दवे

32 विविध समाचार

35 ज़ाकिर नाईक : इस्लाम का नया आतंक

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

जम्मू काश्मीर में पाकिस्तान-प्रेरित आतंकवाद और पिछले डेढ़ महीने से जारी पत्थरबाजी के आन्दोलन ने देश के जनमानस को उद्वेलित कर दिया है। अधिकांश लोग अब चाहते हैं कि किसी भी हालत में इस पर विराम लगे। परदे के पीछे से इस अराजकता को हवा देने वाले पाकिस्तान को भी कठोर संदेश जाये यह सबकी इच्छा थी।

दिनांक 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री मोदी ने पाक-अधिक्रांत जम्मू काश्मीर और बलूचिस्तान का उल्लेख किया तो पूरे देश में उम्मीद की एक लहर उठी। उल्लेख यद्यपि कूटनीतिक सीमाओं के भीतर था, तथापि पिछली सरकारों द्वारा इतना उल्लेख भी कभी नहीं किया गया था, इसलिए इसमें कुछ नयापन था।

देश का सामान्य नागरिक यह नहीं समझ पाता कि पाकिस्तान ग़लत होते हुए भी जिस बात को डंके की चोट पर कहने में नहीं हिचकता, उसे कहने में भारत क्यों संकोच करता है। इसलिए इस नाममात्र के उल्लेख ने भी पूरे देश को उत्साह में ला दिया। इस पर पाकिस्तान की बौखलाहटभरी प्रतिक्रिया ने भी साबित किया कि यह उसके लिए अनापेक्षित था।

दिनांक 9 सितम्बर को जहाँ दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव है, ऐसी स्थिति में, विशेष रूप से जेएनयू-जैसे परिसरों में, जहाँ नीतिगत और वैचारिक विषय चुनाव के मुद्दे बनते हैं, यह एक धारदार बहस को जन्म दे सकता है।

यद्यपि जम्मू काश्मीर का मुद्दा राष्ट्रीय संप्रभुता का मुद्दा है जिस पर पहले दिन से ही न केवल बहस बल्कि निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से नहीं हो सकी। इसके अलावा भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें टालने की नीति देश को भारी पड़ी है। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने की ज़वाबदेही नेतृत्व की है। लेकिन अनिर्णय के चलते तात्कालिक समस्याओं के तात्कालिक समाधान खोजने के चक्कर में सनातन प्रश्नों पर समग्र विचार ही नहीं हुआ, क्रियान्वयन तो दूर की बात है।

शिक्षा-क्षेत्र में भी अनिर्णय की यही स्थिति है। नये-नये संस्थानों की घोषणा करने को पर्याप्त मान लिया गया। वहां की कार्य-संस्कृति और संस्कार-पद्धति, जो संस्थान के लिये ही नहीं बल्कि देश के लिये भी दूरगामी प्रभाव रखती है, पर विचार ही नहीं किया गया। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद संस्थान तो बहुत खुले, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय अथवा विश्वभारती एक भी नहीं बन सका।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना यह सोच कर ही की गयी कि वह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मानक बनेगा। और भी अनेक संस्थान और केन्द्रीय विश्वविद्यालय इसी उम्मीद में गढ़े गये, लेकिन बाद में उन्हें बाज़ार के हवाले कर दिया गया। आज वे अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के लिए सस्ते श्रम का उत्पादन करनेवाले कारखाने बन चुके हैं। इनमें आईआईटी और आईआईएम-जैसे नामी संस्थान भी शामिल हैं जिनसे निकलनेवाली प्रतिभा का बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सेवा में जा रहा है।

भारत की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित और विकास के प्रतिमानों से बहुत दूर है, लेकिन इनके जीवन में सकारात्मक बदल आए, इसके

लिए पहल इन नामी संस्थानों से नहीं होती। सबसे बड़ा पैकेज़ हासिल करने को इन संस्थानों की उपलब्धि के तौर पर स्थापित किया जाता रहा है।

इसकी प्रतिक्रियास्वरूप वामपंथी दलों को इन संस्थानों में पाँव रखने की जगह मिली और आज ये संस्थान सारी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का केन्द्र बन गए हैं। देश में चल रहे हिंसक आंदोलनों का सार्वजनिक समर्थन करने का काम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कथित समर्थक यह समूह कर रहे हैं। भारतीय दृष्टि और भारतीय दर्शन को चोट पहुँचानेवाले इन समूहों की मदद से ही भारत-विरोधी बाहरी शक्तियों को देश में पाँव पसारने का मौका मिलता है। यही लोग पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय की पत्रिका में वैमनस्य फैलानेवाली सामग्री छापते हैं। रोहित वेमुला की आत्महत्या को अपने राजनैतिक हितों के लिए इस्तेमाल करते हैं और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में सुरक्षा जाँच के लिए पुलिसकर्मियों के प्रवेश पर आसमान सर पर उठा लेते हैं।

भारत की एकता और अखण्डता की बात करने के साथ ज़रूरी है कि भारत को उसके सही संदर्भ में समझा जाये। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालयीन पाठ्यक्रम में भारत की पूरी जानकारी देश की आनेवाली पीढ़ी को दी जाये। लाल किले की घोषणा परिसरों में चर्चा का बिन्दु बने, यह काम परिषद् कार्यकर्ताओं को करना होगा। इस अंक में संकलित लेख इसके लिए आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं।

रियो ओलम्पिक में भारतीय खिलाड़ियों का एक बड़ा दल गया, किन्तु केवल दो पदकों पर संतोष करना पड़ा। ज़रूरी है कि देश क्रिकेट के बुखार से बाहर आये और अन्य खेलों को भी गंभीरता से ले और उसके खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराये। ख़ास तौर पर खेलों में प्रशासनिक और राजनैतिक हस्तक्षेप को दूर किए बिना इनका उद्धार संभव नहीं।

सितम्बर माह परिसर-गतिविधियों के लिए महत्त्वपूर्ण है। अनेक परिसरों में छात्र संघ चुनाव की गहमा-गहमी रहेगी, वहीं सदस्यता-अभियान अपने चरम पर होगा। शिक्षक दिवस, विश्वविजय दिवस और भारतीय भाषा दिवस 14 सितम्बर भी इस माह में ही है। एकात्म मानववाद के प्रणेता स्व. पं. दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशताब्दी का समापन 25 सितम्बर, 2016 को होगा। यह सभी आयोजन अभाविप वर्षों से निरंतर करती रही है, इस बार भी होंगे।

नये सत्र में नये लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नयी उमंग के साथ हम सब आगे बढ़ें, इस मंगलकामना के साथ,

आपका,
संपादक

जम्मू काश्मीर

"आतंक से समझौता प्रधानमंत्री का लालकिले से

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पाक-अधिक्रांत जम्मू काश्मीर के साथ ही बलूचिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया। साथ ही चीन को भी परोक्ष संकेत दे दिया कि यदि वह बलूचिस्तान होकर अपना व्यापार शांतिपूर्वक चलाना चाहता है तो गिलगित-बल्तिस्तान में भारतीय हितों को ताक पर रख कर ऐसा नहीं हो सकता।

■ आशुतोष भटनागर

बात बुरहान वानी की मौत के साथ शुरू ज़रूर हुई, पर खत्म नहीं होगी। कहते हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जायेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पाक-अधिक्रांत जम्मू काश्मीर के साथ ही बलूचिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया। साथ ही चीन को भी परोक्ष संकेत दे दिया कि यदि वह बलूचिस्तान होकर अपना व्यापार शांतिपूर्वक चलाना चाहता है तो गिलगित-बल्तिस्तान में भारतीय हितों को ताक पर रख कर ऐसा नहीं हो सकता।

हिज़बुल मुजाहिद्दीन का कुख्यात आतंकी बुरहान वानी दक्षिण काश्मीर के बमडूरा-कोकरनाग में अपने दो साथियों सरताज और मासूम शाह सहित सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। हिजबुल का पोस्टर ब्वाय बना यह आतंकी सोशल मीडिया पर सक्रिय था और आतंकियों की नयी पीढ़ी को जोड़ने में इसकी मुख्य भूमिका थी।

बुरहान के परिवार के अन्य छः लोग भी जेहाद के रास्ते पर जा चुके हैं। बुरहान का बचपन भी बन्दूकों के साये में ही बीता। इसलिये 15 वर्ष की उम्र में उसने भी बन्दूक थाम ली। माना जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में उसने लगभग 100 युवाओं को आतंकी बनाया था। सरकार ने उस पर दस लाख रुपये का इनाम रखा था।

बुरहान का काम संघर्ष करना नहीं था। शायद ही उसने कभी अपनी रायफलों से काम लिया हो। किन्तु आभासी दुनिया में उसका कद इतना बड़ा हो गया जिसके चलते नौजवानों का एक वर्ग उसे अपना आदर्श मानने लगा। सोशल मीडिया आभासी दुनिया में आतंक का रास्ता भी ग्लैमर भरा हो गया है।

नहीं करेगा भारत"

पाकिस्तान को कूटनीतिक संदेश

बुरहान की मण्डली के नये आतंकवादियों ने भले ही सुरक्षा बलों के साथ आमने-सामने की लड़ाई कभी न लड़ी हो, लेकिन सफल के साथ फोटो खिंचाना और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना संभवतः उन्हें मानसिक संतुष्टि देता होगा। इन लोगों ने पिछली पीढ़ी के आतंकवादियों से अलग न तो अपने चेहरे छिपाए और न ही नाम-पते। उनका पूरा प्रोफाइल फेसबुक पर मौजूद है।

यहाँ इस व्यवहारिक तथ्य को भी समझना होगा कि काश्मीर में शिक्षा अधिक है और रोज़गार बहुत कम। परिणामस्वरूप जब उनके बौद्धिक सपने पूरे नहीं होते तो वे भावनात्मक मुद्दों की ओर आकर्षित होते हैं। बुरहान का काम ऐसे ही लोगों को जोड़ना था।

हिजबुल कमांडर की मौत की ख़बर फैलते ही दक्षिण काश्मीर के विभिन्न हिस्सों में लोग विरोध-प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आये। उसके जनाज़े में हज़ारों लोग जुटे। इसमें आतंकी भी मौजूद थे और बताया जाता है कि उन्होंने उसे हवा में सलामी दी। प्रतिबंधित झण्डे भी फहराये गये। इसके अतिरिक्त चालीस से ज्यादा जगहों पर बिना उसके शव के भी 'नमाज-ए-जनाजा' का आयोजन किया गया।

मातम के बाद सभी जगहों पर हिंसक भीड़ ने 'वेस्सु-कुलगाम' में हिंदुओं और सिखों के घरों पर हमला किया। सुरक्षा बलों के बंकर, पुलिस थाने, सरकारी संस्थान, वाहन आदि जलाए गये। पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर हथियार लूटे गये। एक पुलिस अधिकारी के घर में घुसकर उसकी पत्नी और बेटी को पीटा गया तो दूसरे को सरकारी वाहन सहित झेलम में फेंक दिया गया जिससे उसकी मौत हो गयी। उपद्रवियों ने एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा। पिछले पाँच दिनों में 70 एम्बुलेंसें क्षतिग्रस्त हुई हैं।

पूरा घटनाक्रम जिस तरह से सामने आया है, उससे इसे स्वतःस्फूर्त या बुरहान की मौत से गुस्साए लोगों की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह पूरी तरह नियोजित और संगठित हिंसा है। कहा जा सकता है कि इसकी योजना पहले से तैयार थी। केवल मौके का इन्तजार था जो उन्हें बुरहान की मौत ने दे दिया। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ है।

वर्ष 2016 में लगभग 80 आतंकवादी मारे गए हैं। सभी के

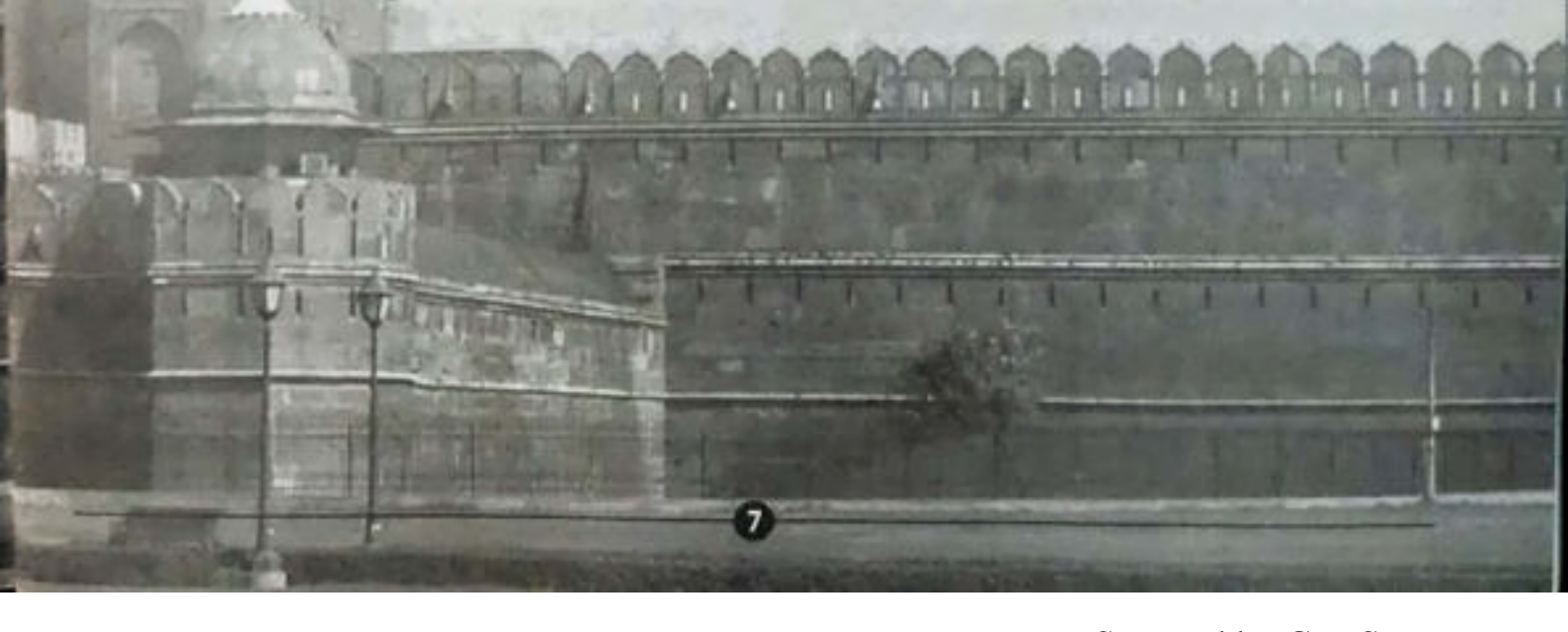

जनाज़ों में भारी भीड़ जुटी है। किन्तु यदि इसका विश्लेषण किया जाए, तो जनाज़ों में जुटनेवाली भीड़ तमाशबीन ज्यादा है। उनमें से मुट्ठीभर ही हैं जो पत्थरबाजी में शामिल होते हैं। लेकिन अलगाववादियों ने इन जनाज़ों को शक्ति-प्रदर्शन का जरिया मान लिया है जिसे दिखाकर वे दिल्ली को डराना चाहते हैं और पाकिस्तान को यह अहसास कराना चाहते हैं उनकी ताकत अभी भी बनी हुई है।

पिछले कुछ वर्षों में ज़मीनी स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया। आतंकवाद के प्रति अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है और अब कथित उग्रवादी संगठनों के लिये पहले जैसी सहानुभूति कहीं नहीं बची है। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है और दुनिया के ज्यादातर देश इसके साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। दूसरी ओर कश्मीरी युवाओं का पाकिस्तान से बहुत हद तक मोह भंग हुआ है। वे समझ चुके हैं कि पाकिस्तान असफल राष्ट्रों की श्रेणी में जा खड़ा हुआ है।

गिलगित-बल्तिस्तान और पाक-अधिक्रांत जम्मू काश्मीर– दोनों ही क्षेत्र वैधानिक रूप से भारत के अंग हैं। और जब अभिन्न अंग कहा जाता है तो वहाँ के निवासी, जो 26 अक्तूबर, 1947 को इस क्षेत्र में रह रहे थे, और उनके वंशज भी भारत के नागरिक का हक रखते हैं। इसलिये यदि ये नागरिक पाकिस्तान के अत्याचारों और लूट-खसोट से त्रस्त हैं तो भारत की यह जिम्मेदारी बनती है कि उनकी चिन्ता करे।

भारत को अब 90 के दशक की रक्षात्मक मानसिकता से बाहर आना होगा तथा भीतरी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे पाकिस्तानी दुष्प्रचार पर प्रतिक्रिया देने की आदत बदलनी होगी। राज्य में राष्ट्रवादी शक्तियों को सबल बनाना तथा संबंधित पक्षों के बीच ठोस नेटवर्क स्थापित कर अलगाववादियों तथा शरीफ को यह बताने के लिए कि नियति का चक्र घूम चुका है, प्रधानमंत्री मोदी का यह उल्लेख आवश्यक था।

काश्मीर में जो दशकों से चल रहा है और हाल के दिनों में उसमें जिस प्रकार की तेजी आई है, उससे जनमानस में यह बात पल रही थी कि बस बहुत हो गया। अब अलगाववादियों और उन्हें पीछे से समर्थन देनेवाले पाकिस्तान को कठोर संदेश दिया जाना चाहिये। मोदी ने वही किया जिसकी उम्मीद जनता उनसे कर रही थी।

कुछ भी हो, पाक-अधिक्रांत जम्मू काश्मीर की बात भारत की ओर से पहली बार इतनी मज़बूती के साथ कही गई है। अब काँग्रेस कह रही है कि नरसिंह राव भी ऐसा ही प्रस्ताव लाये थे। यह ठीक है लेकिन वे तब लाए थे जब पाकिस्तान के जाल में उलझ ही गए थे और उससे बचने के लिये यह करना ज़रूरी हो गया था। साथ ही काँग्रेस-प्रवक्ताओं को यह भी याद रखना चाहिये कि उस स्थिति में भाजपा न केवल उनके साथ खड़ी रही अपितु इसकी काट के लिए नरसिंह राव ने प्रतिनिधिमण्डल के अध्यक्ष के रूप में तत्कालीन नेता-प्रतिपक्ष श्री अटल विहारी वाजपेयी को ही चुना था।

भारत और भारतीय राजनीति– दोनों ही अब नरसिंह राव के दौर से बहुत दूर निकल आए हैं। आज देश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। मोदी के नेतृत्व के बारे में भी यह धारणा बनी है कि निर्णय लेने पर वे इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई बात का असर कहीं ज्यादा है।

गिलगित-बल्तिस्तान और पाक-अधिक्रांत जम्मू काश्मीर– दोनों ही क्षेत्र वैधानिक रूप से भारत के अंग हैं। और जब अभिन्न अंग कहा जाता है तो वहाँ के निवासी, जो 26 अक्तूबर, 1947 को इस क्षेत्र में रह रहे थे, और उनके वंशज भी भारत के नागरिक का हक़ रखते हैं। इसलिये यदि ये नागरिक पाकिस्तान के अत्याचारों और लूट-खसोट से त्रस्त हैं तो भारत की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि उनकी चिन्ता करे।

पाकिस्तान इस क्षेत्र में वही सब हथकण्डे दोहरा रहा है जो

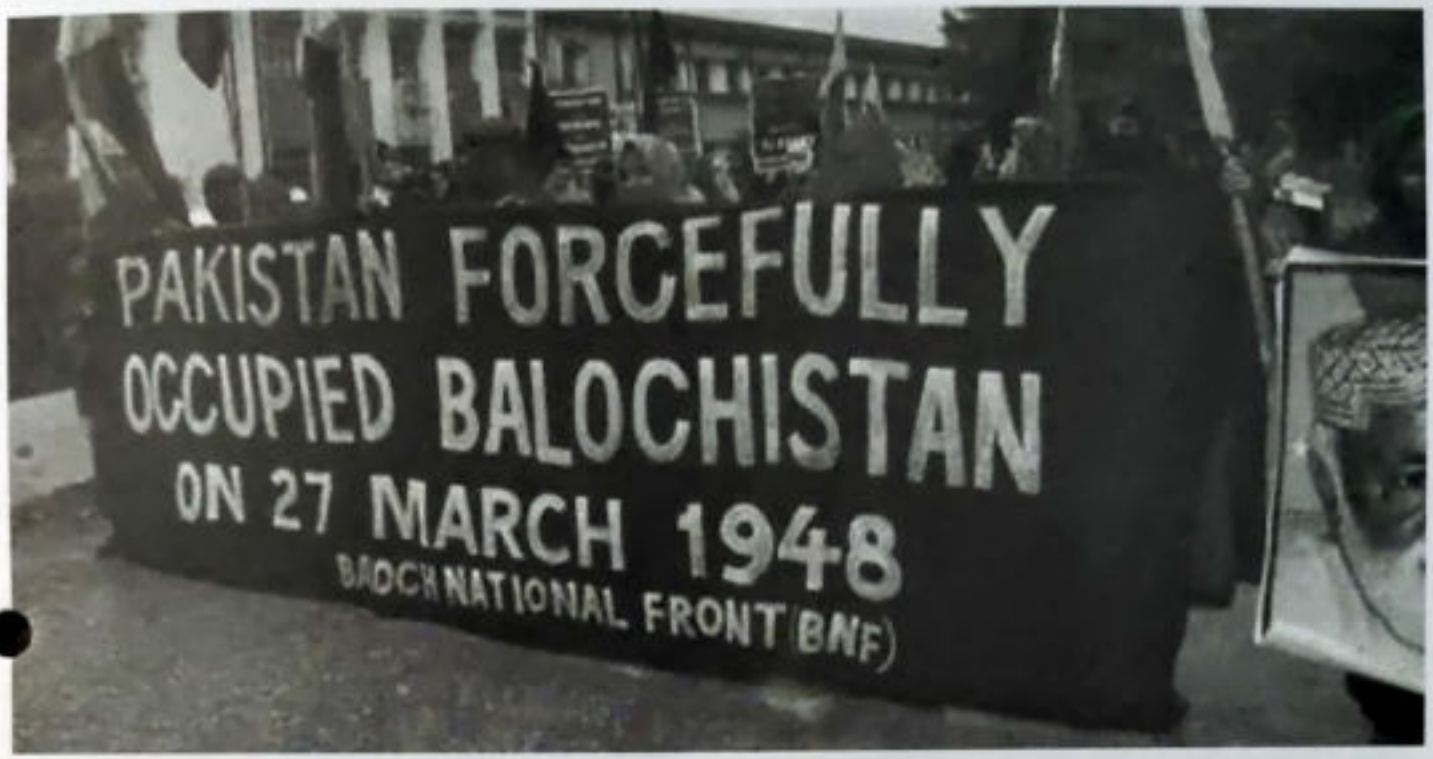

चीन दशकों से तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान और इनर मंगोलिया में अपना रहा है। जिस तरह चीन तिब्बत में चीनी जनसंख्या को बसाकर मूल तिब्बतियों को जातीय तौर पर अल्पसंख्यक बना रहा है और जनसांख्यिक बदलाव के द्वारा वहाँ अपने विरोध को प्रभावहीन बना रहा है, वही कार्य पाकिस्तान गिलगित-बल्तिस्तान में पंजाबीभाषी एवं पख्तून सुन्नी मुस्लिम जनसंख्या को बसाकर और वहाँ के व्यापार और नौकरियों में उनकी संख्या बढ़ाकर करना चाहता है।

पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेन्सी इस इलाके में आतंकवादियों के प्रशिक्षण-शिविर चलाती है, वहीं वह स्थानीय निवासियों को उनके कबीलाई रीति-रिवाजों और परम्पराओं से दूर कर उनके अरबीकरण में जुटी है। इसके लिये वह आतंकवादी गुटों का भी सहारा लेती है। इसका विरोध करनेवाले स्थानीय नेताओं को राजद्रोह के आरोप में जेलों में ठूँस दिया जाता है और उनका उत्पीड़न किया जाता है।

आतंकवादियों के समर्थन को सीमित और निष्प्रभावी करना होगा।

राज्य के सभी भागों की शेष देश के साथ सामाजिक-आर्थिक एकात्मता स्थापित हो, इसके लिए राज्य और शेष देश के बीच परस्पर संवाद को बढ़ाना होगा। घाटी के लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि संवाद बढ़ाने की यह प्रक्रिया उनके हित में है और इसके पीछे कोई राजनैतिक विचार नहीं बल्कि सदियों की दूरी को पाटना ही है। इसे लागू करने में अलगाववादियों की ओर से विरोध स्वाभाविक है किन्तु जनता से सीधा संवाद अपेक्षित परिणाम दे सकता है। तात्कालिक विरोध-प्रदर्शनों से कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में निपटना स्वाभाविक है, किन्तु अब समय आ गया है कि देश जम्मू काश्मीर को लेकर एक ठोस नीति बनाये और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ उसे लागू करे।

दिनांक 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इसकी ओर संकेतमात्र ही किया और हंगामा हो गया। लंबे भाषण में उन्होंने देश के प्रायः हर प्रश्न को संबोधित किया। लेकिन बलूचिस्तान, गिलगित और पाक-अधिक्रांत काश्मीर के लोगों द्वारा दिए गए धन्यवाद का आभार जतानेवाला एक वाक्य कई दिनों बाद भी आज चर्चा में बना हुआ है। ऐसा इसलिये क्योंकि इस एक वाक्य ने पाकिस्तान की नीयत और नियति– दोनों पर सवाल खड़ा कर दिया है।

यह तो साफ़ है कि इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस को काश्मीर के जंगजुओं के लिये समर्पित करने के बाद ही इसे संबोधन में शामिल किया गया।

यदि भारत का प्रधानमंत्री लालकिले से उनका आभार जताता है तो इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है। यहाँ बात केवल उनके उल्लेख की ही नहीं है। पाकिस्तान से निरंतर युद्ध की मुद्रा में रहते

हुए भी न तो उसके कब्ज़ेवाले हिस्से पर कभी ठोस बात की गयी और न ही वहाँ के निवासी जो गत सात दशक से भारत में विभिन्न स्थानों पर विस्थापित के रूप में रह रहे हैं, के पुनर्वास की बात सिरे चढ़ी। इन उल्लेखों का कोई ठोस असर तब तक हो भी नहीं सकता जब तक धरातल पर इसके लिये प्रयास न हों।

पूर्ववर्ती जम्मू काश्मीर रियासत के मीरपुर-मुज़फ्फराबादवाले हिस्से को, जिस पर अक्तूबर 1947 में आक्रमण कर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया था, को 'गुलाम काश्मीर' पुकारने की शुरूआत प्रतिक्रियास्वरूप हुई। पाकिस्तान ने लगभग 13 हज़ार वर्ग किमी विस्तृत इस भू-भाग पर मुस्लिम लीग के लोगों के साथ साजिश कर एक कथित आज़ाद सरकार का गठन करा दिया ताकि दुनियाँ के सामने इसे स्थानीय विद्रोह साबित किया जा सके। उसने इसे आज़ाद जम्मू काश्मीर और भारत के नियंत्रणवाले क्षेत्र को गुलाम काश्मीर कहना शुरू किया। प्रतिक्रिया में भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के कब्ज़ेवाले क्षेत्र को 'गुलाम काश्मीर' कहना शुरू कर दिया। सच तो यह है कि न तो वह आज़ाद काश्मीर है और न ही यह गुलाम। तकनीकी और संवैधानिक दृष्टि से जम्मू काश्मीर एक सम्पूर्ण इकाई है जो भारत का अभिन्न अंग है।

इसके साथ ही, इस तथ्य को भी नहीं भुलाया जाना चाहिये कि कथित आज़ाद या गुलाम काश्मीर ही संघर्ष का केन्द्रबिन्दु नहीं है। यह पाकिस्तान की कूटनीतिक चाल है जिसे 40, 50 और 60 के दशकों में अंतरराष्ट्रीय सहमति हासिल थी। इसके साथ ही 'गिलगित-बल्तिस्तान' की लगभग 65 हज़ार वर्ग किमी भूमि पाकिस्तान के अवैध कब्ज़े में है। यह लद्दाख का इलाका है और इसका काश्मीर से प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। रणनीतिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इस पर चर्चा से बचने के लिये ही कथित पीओके (POK) का मसला हमेशा उछाला जाता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 1962 के युद्ध के समय चीन ने अक्साईचिन के लगभग 36 हज़ार वर्ग किमी पर कब्ज़ा कर लिया था। 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुए एक समझौते के तहत अक्साईचिन से लगनेवाले पाक-अधिक्रांत जम्मू काश्मीर के एक हिस्से 'शक्सगाम घाटी' को चीन के अधिकार में दे दिया गया। चीन ने इस पर काराकोरम हाइवे का निर्माण किया है। फिर भी भारत की ओर से कड़ा संदेश देने की कोशिश कभी नहीं की गयी, कभी प्रतिरोध नहीं किया गया। भारत की चुप्पी ने हमेशा उनके हौंसले को बढ़ाया।

सरकार के लिए यह उचित समय है जब जम्मू कश्मीर का मामला पूरी तौर पर सुलझा लिया जाय। इसके लिए पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी देश की सहमति अथवा मध्यस्थता की नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। यदि केन्द्र सरकार यह दृढ़ता और साहस दिखाती है तो पूरे देश का विश्वास उसे प्राप्त होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ■

अभाविप का विधानसभा घेराव पुलिस ने भाँजीं लाठियाँ

बदहाल शिक्षा-व्यवस्था और महिला-उत्पीड़न के ख़िलाफ विद्यार्थी परिषद् का प्रदर्शन

उत्तरप्रदेश की बदहाल शिक्षा-व्यवस्था, विश्वविद्यालयों में मनमानी शुल्क-वृद्धि तथा महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की घटनाओं के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने लखनऊ विधानसभा का घेराव किया। 17-सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के ख़िलाफ सड़कों पर उतरे अभाविप-कार्यकर्ताओं को इस दौरान पुलिस की बर्बरता का भी शिकार होना पड़ा।

अखिलेश सरकार की प्रभावहीन व्यवस्था और शिक्षा के गिरते स्तर के ख़िलाफ नारेबाजी कर रहे छात्रों पर पुलिस ने उस [illegible] लाठियाँ भाँजीं, जब वे शान्तिपूर्वक अपना विरोध जता रहे थे। प्रशासन की दमनकारी नीति का नतीज़ा यह रहा कि दर्जनों की संख्या में अभाविप कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस इसके बाद भी नहीं रुकी और उसने छात्रों को व्यवस्था में बाधा पहुँचाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया।

अभाविप के अवध प्रात मंत्री रमन सिंह ने बताया अभाविप देश व छात्र-हित में विभिन्न प्रकार के समय-समय पर कदम उठाती रही है। इसी क्रम में परिषद् के कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय पर इकट्ठे होकर शिक्षा-व्यवस्था और छात्र-हित से जुड़ी 17-सूत्रीय मांगपत्र लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुँचे थे। कार्यकर्ता शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर बर्बर तरीके से लाठी चार्ज किया।

परिषद् की मांगें

- छात्राओं और महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोका जाए।
- सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय का शैक्षिक कैलेंडर सत्र के शुरू में घोषित किया जाए।
- प्रदेश सरकार तय करे कि अगस्त माह में सभी विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव हो जाएँ।
- छात्रों की छात्रवृत्ति समय से मिले, इसका उचित प्रबंध हो।
- सभी विश्वविद्यालयों, सरकारी एवं अर्ध-सरकारी महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति की जाए।
- पिछले सालों में हुई छात्रवृत्ति-धाँधली की जांच कर दोषियों के ख़िलाफ कार्रवाई की जाए।
- छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सभी ज़िलों में नये सरकारी महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए।
- तकनीकी शिक्षण संस्थानों में हो रही मनमानी शुल्क-वसूली पर रोक लगाई जाए।
- प्रदेश की सभी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में मैनेज़मेंट कोटे से भरी जानेवाली सीटों को समाप्त किया जाए।
- प्रदेश में फैले नकल माफियाओं के जाल पर लगाम लगाई जाए।
- प्रदेश के विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में छात्र-समस्या निवारण-केंद्र स्थापित किया जाए।

वहीं, प्रदेश संगठन मंत्री सत्यभान सिंह ने कहा पुलिस के इस रवैये से कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। पुलिसिया बर्बरता को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया है। मगर अब तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ■

आई फील सेफ

महिला-सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया एप

महिला-सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एमएसएआई मोबाईल कंपनी द्वारा 'आई फील सेफ- सेफ्टी का पावर बटन' मोबाइल एप बनाया गया है। इसकी लॉन्चिंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् और निर्भया ज्योति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में की गयी। इस एप के जरिए ज़रूरत के समय महिलाएँ/ छात्राएँ अपने लिए मदद मांग सकेंगी।

एमएसएआई कंपनी की व्यापार-प्रमुख भावना कुमारी ने एप के बारे में बताते हुए कहा कि पहले इस एप को डाउनलोड करें और अपने मोबाईल में इन्स्टॉल करें। मोबाइल का ऑफ़ बटन, पैनिक बटन का काम करता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई महिला / छात्रा मुसीबत में है, तो इसके ऑफ़ बटन को पाँच बार दबाने पर उसके परिजनों के पास संदेश चला जायेगा कि आपका बच्चा मुसीबत में है तथा इससे लोकेशन का पता भी आसानी से चल जायेगा। इस एप को विशेष रूप से महिलाओं के साथ हो रही छेड़खानी, दुराचार-जैसी घटनाओं से बचने के लिए बनाया गया है।

कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाइयों के कलाई पर राखी बाँधते समय वादा लें कि जिस तरह आप मेरी रक्षा करते हो, उसी तरह दूसरे की बहन की भी रक्षा करोगे। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरी है, जिसके लिए अभाविप हमेशा तत्पर रहता है। एप को बनानेवाली कंपनी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि यह एप महिला-सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

इस मौके पर निर्भया की माता श्रीमती आशा देवी ने कहा कि एमएसएआई कंपनी द्वारा बनाया गया यह एप छात्राओं को संबल देगा कि वह अब घर के बाहर भी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से चल रहे निर्भया ज्योति ट्रस्ट और अभाविप के सहयोग से इस प्रकार के एप की लॉन्चिंग ट्रस्ट की उपयोगिता को और बढ़ाता है। ट्रस्ट की स्थापना ही हर लड़की को सक्षम जीवन मिले इस उद्देश्य से की गयी। छात्राएँ बिना हिंसा और छेड़छाड़ के डर से घर के बाहर निकल सकें इस दिशा में 'आई फील सेफ - सेफ्टी का पावर बटन' एप एक सराहनीय कदम है।

वहीं अभाविप के प्रदेश मंत्री भरत खटाना ने कहा कि आये दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म, छेड़खानी, दुर्व्यवहार-जैसी घटनाएँ देखने को मिलती रहती हैं। ऐसे समय में आई फिल सेफ एप महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा। ■

Rio2016

पदक कम, दिल ज्यादा जीते

■ आकाश कुमार राय

एक खिलाड़ी के तौर पर ओलंपिक में भाग लेना, देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना और खेल के वैश्विक स्तर पर अपने प्रदर्शन से सबको चौंकाना– ये तीन बातें किसी पदक को जीतने से ज़्यादा मायने रखती हैं। भारत के संदर्भ में तो यह पूर्णतया फीट भी बैठती है; क्योंकि भले पदकों की श्रेणी में भारत कमतर रहा, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने दिल ज़रूर जीते।

रियो ओलंपिक के आगाज़ के साथ ही हमारी उम्मीदें भी बलवती होती गयीं। हमें भरोसा था कि 117-सदस्यीय भारतीय खिलाड़ियों का दल पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए इस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतेगा। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए, वैसे-वैसे उम्मीद की मज़बूत दीवारें भी दरकने लगीं। रियो में 11 दिन तक भारत की झोली खाली रही। 12वें दिन की शुरूआत भी कुछ अलग नहीं रही। फ्रीस्टाइल महिला कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक अपनी बाउट हार चुकी थीं। विनेश फौगाट पहला मुकाबला जीतकर, घायल होने की वजह से बाहर हो चुकी थी। ऐसे में जब देशवासी सो रहे थे और भारत की उम्मीदें ओझल-सी हो रही थीं, उस बीच ख़बर आई कि साक्षी जिस रूसी खिलाड़ी कोबलोवा झोलोबोवा वालेरिया से हारी थीं, वह फाइनल में पहुँच गयी। इसके बाद नियम के मुताबिक साक्षी को रेपचेस के लिए खेलने का मौका मिला। इस एक अवसर को साक्षी ने देश का मान बढ़ानेवाला पल बना दिया और किर्गिस्तान की पहलवान को पटखनी दी। साक्षी की इस जीत ने खिलाड़ियों और देशवासियों को निराशा से उबारने का काम किया।

इसके बाद भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु ने इतिहास रचते हुए ओलिंपिक में पहली बार किसी भारतीय

महिला द्वारा रजत पदक जीतने का गौरव हासिल किया। महिला एकल बैडमिंटन के सेमीफाइनल में सिंधु ने विश्व की नंबर छह खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा को मात देकर फाइनल में जगह बनायी। लेकिन विश्व की नंबर एक खिलाड़ी स्पेन की मारिन कैरोलिना को जबरदस्त टक्कर देने के बावजूद सिंधु मैच नहीं जीत सकीं।

साक्षी और सिंधु की जीत ने जहाँ देश को खुश किया, वहीं रियो ओलंपिक की पदक तालिका में भी भारत को शुमार कराया। दीपा कर्माकर, विनेश फोगाट और सानिया मिर्जा भले मेडल जीतने से चूक गई हों, लेकिन उनका असाधारण खेल नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। यहाँ विनेश फौगाट का खासतौर से ज़िक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने 48 किग्रा वर्ग के प्री-क्वार्टर फाइनल में रोमानिया की एलिना एमिलिया को 5.01 मिनट में 11-0 के अंतर से पराजित किया। विनेश की चीते-सी फुर्ती इस बाउट में जिसने भी देखी, हैरान रह गया, लेकिन शायद भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। विनेश फौगाट क्वार्टर फाइनल में बुरी तरह चोटिल हो गईं और मैच के बीच उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना पड़ा। इसके कारण चीन की सुन यानान को विजयी घोषित किया गया।

इससे पहले, 23 साल की जिमनास्ट दीपा कर्माकर केवल 0.15 प्वाइंट के मामूली अंतर से मेडल से चूकीं। वह वल्ट इवेंट में चौथी पोजिशन पर रहीं, लेकिन उनके अदम्य खेल ने उन्हें हीरो बना दिया। ओलंपिक के 120 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब कोई भारतीय एथलीट जिम्नास्टिक्स के फाइनल तक पहुँचा। बड़ी बात यह रही कि जिम्नास्टिक की सभी पाँच क्वालिफिकेशन सबडिवीजन स्पर्धा के बाद दीपा वल्ट में आठवें स्थान पर रहीं, जो फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए आखिरी स्थान था। इस स्थान से खुद को चौथे नंबर तक पहुँचाना कोई आसान काम नहीं था। वहीं, ललिता बाबर ने महिलाओं की 3,000 मीटर स्टीपलचेज के फाइनल में पहुँचनेवाली पहली भारतीय बनी। पदक जीतने के करीब पहुँचकर ललिता ने यह तो दर्शा दिया कि उनमें हौसले की कमी नहीं है।

आठ साल पहले बीजिंग ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचनेवाले स्टार निशानेबाज अभिनव बिंद्रा इस बार 10 मीटर एअर राइफल स्पर्धा में इतिहास रचने से चूक गए। बंदूक में खराबी को वजह बतानेवाले बिंद्रा स्पर्धा के फाइनल में चौथे स्थान पर रहे। हालांकि बिंद्रा ने अपने प्रदर्शन से उम्मीद तो जगा दी थी, मगर आखिरी राउंड्स में मेडल की रेस से वो बाहर हो गए। वहीं, भारत की तरफ से पदक की सबसे बड़ी उम्मीद सानिया मिर्ज़ा का हारना देश के साथ-साथ उनके लिए दुखद रहा। सानिया एक के बाद एक मुकाबले जीतते हुए आगे बढ़ी थीं। लेकिन क्वार्टर फाइनल की बाधा को वह पार नहीं कर सकीं और कांस्य पदक का सपना टूट गया। पुरुष हॉकी का भी कमोबेस यही हाल रहा। 36 साल बाद ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में जगह बनानेवाली भारतीय टीम आगे नहीं बढ़ सकी।

पदक को लेकर भारतीय उम्मीद के एक दीप पहलवान नरसिंह यादव भी थे लेकिन डोप टेस्ट के मकड़जाल में फँसने के कारण उन पर चार साल का प्रतिबंध लग गया जिससे वह ओलंपिक के मैदान में भी नहीं उतर सके। रियो में भारतीय खिलाड़ियों का दल 15 खेलों में प्रतिभाग करने गया था, मगर सच्चाई तो यह है कि कुछ खेलों को छोड़कर शेष में भारत की नुमाइंदगी बस नाममात्र की रही। जूडो, जिमनास्टिक, नौकायन और भारोत्तोलन-जैसे खेलों में बड़े नामों के क्वालीफाई नहीं कर पाने की स्थिति में टीम का चयन बस कोटापूर्ति ही दिखी। वहीं, 12 साल बाद ओलंपिक में वापसी करनेवाले गोल्फ को लेकर भी ऐसा ही कुछ मामला रहा। कई बड़े खिलाड़ियों की रियो ओलंपिक में दिलचस्पी नहीं दिखाने की वजह से अनिर्बान लाहिड़ी और अदिति अशोक पर दाँव खेला गया, जो पदक जीतने की इच्छाशक्ति के लिहाज़ से नाकाफ़ी रहा।

सवा अरब भारतीयों की उम्मीद लेकर रियो पहुँचे खिलाड़ियों द्वारा सिर्फ़ दो पदक जीतना दुःखी तो करता है, मगर रियो ओलंपिक के समापन के साथ एक उम्मीद भी जगती है कि चार साल बाद जब फिर से विश्वभर के खिलाड़ियों का जमघट लगेगा, तो भारत बेहतर करेगा। आखिर अपने खिलाड़ियों से बेहतरी की उम्मीद हो भी क्यों न। जब खिलाड़ियों की मिलनेवाली सुविधाओं में इज़ाफा हो रहा हो। देशी और विदेशी कोच के साथ व्यक्तिगत कोच, मसाजर और ट्रेनर खिलाड़ियों को निखारने में लगे हों। खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम (टॉप्स) स्कीम के तहत खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर 180 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँ, तब पदक की उम्मीद करना तो लाज़मी हो जाता है।

(लेखक राष्ट्रीय छात्रशक्ति पत्रिका के संपादन मंडल सदस्य हैं)

लंबित मांगों को लेकर अभाविप ने खोला मोर्चा

32-सूत्रीय मांगों के साथ मंत्रालय घेरने निकले कार्यकर्ता, हुई गिरफ़्तारी

रायपुर। उच्च शिक्षा में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्रालय घेरने की योजना फलीभूत नहीं हो सकी। उच्च शिक्षा विभाग एवं शैक्षणिक संस्थाओं की सुविधाओं में व्यापक बदलाव की मांग को लेकर अभाविप कार्यकर्ता मंत्रालय का घेराव करने निकले थे। मगर पुलिस ने छात्रों के भारी संख्या बल को देखते हुए मंत्रालय के पहले ही इन्हें रोक दिया।

इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गयी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभाविप कार्यकर्ताओं के साथ परिषद् के राष्ट्रीय महामंत्री विनय बिरदे, राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री के.एन. रघुनन्दन को भी गिरफ़्तार कर लिया।

अभाविप-कार्यकर्ताओं को मंत्रालय का घेराव करने से रोकने के पश्चात् छात्रों के प्रतिनिधिमण्डल ने उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय से भी मिलने की भी कोशिश की। लेकिन बाद में सरकार के साथ वार्ता के लिए 13 अगस्त की तिथि तय हुई। प्रदर्शन के दौरान आयोजित सभा में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री विनय बिदरे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री के.एन. रघुनन्दन और क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। अधिकारियों ने शिक्षा की गुणवत्ता-सुधार और उच्च शिक्षा विभाग में सुविधाओं को लेकर अपनी 32-सूत्रीय मांगों पर ही जोर दिया। पदाधिकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो परिषद् उग्र आंदोलन करेगी।

बता दें कि अभाविप का यह प्रदर्शन कॉलेजों में जनभागीदारी निधि का 50 प्रतिशत छात्र संघ निधि के रूप में खर्च करने, विश्वविद्यालय के निर्णय में छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करने, निजी विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच करने, विश्वविद्यालय में केंद्रीय प्लेसमेंट सिस्टम लागू करने, कॉलेजों में सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वर्तमान शैक्षणिक स्थिति में सुधार, ठोस शिक्षा नीति, छात्रों को रोज़गार, निजी विद्यालय और महाविद्यालयों द्वारा छात्रों का शोषण रोकने जैसी कई मांगों को लेकर किया गया।

ऋषिकेश में अभाविप की जीत, अमित पंवार बने अध्यक्ष

ऋषिकेश। प्रदेश के एकमात्र ऑटोनोमस कॉलेज पं. ललित मोहन शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने अध्यक्ष पद पर जीत का परचम लहराया। परिषद् के अमित पँवार ने एनएसयूआई के शिवम गुप्ता को 541 मतों से हराया। अमित पँवार को 1,252 मत मिले जबकि एनएसयूआइ के शिवम गुप्ता को मात्र 711 मत मिले।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआइ के शुभम गौड़ निर्विरोध निर्वाचित हुए। सचिव पद पर आर्यन ग्रुप के दीपक रावत तथा सह-सचिव पद पर एनएसयूआई के सौरभ वर्मा विजयी रहे। जबकि कोषाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर भी एनएसयूआई का कब्जा रहा। राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में 76.7 प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने मतदान किया।

इस जीत के साथ ही अभाविप ने पाँच वर्ष के वनवास को समाप्त किया। इससे पहले, वर्ष 2010 में परिषद् के धीरेंद्र कुमार चुनाव जीते थे। उसके बाद से एनएसयूआई ही अध्यक्ष पद का चुनाव जीतती रही। अभाविप के प्रदेश संगठन मंत्री बृजेश बनकोटी ने कहा कि छात्रसंघ को लेकर समाज में जो प्रतिकूल भावना पनप रही है, उसे विद्यार्थी परिषद् इस वर्ष बदलने का काम करेगी। विद्यार्थी परिषद् महाविद्यालय के लिए एक नयी मिसाल खड़ी करेगी।

एक बेहतर कदम, लेकिन समस्याओं का निराकरण जरूरी

■ डॉ. अश्विनी महाजन

पूरे देश भर में वस्तुओं और सेवाओं पर सभी प्रकार के करों को समाप्त करते हुए, जीएसटी (वस्तु-सेवाकर) के नाम से एक ही कर लागू करने का नीति-निर्माताओं का सपना तब पूरा हो गया जब राज्यसभा ने 4 अगस्त को इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि काँग्रेस पार्टी के विरोध के चलते राज्यसभा में जीएसटी बिल को पारित करना असंभव दिखाई दे रहा था। इस बीच सत्ताधारी एनडीए और काँग्रेस के बीच सहमति होने से अब जीएसटी के रास्ते में रुकावटें खत्म हो गईं; क्योंकि लोकसभा में इसे पारित करना महज एक औपचारिकता ही बच गई थी, जो बाद में पूरी हो गयी। गौरतलब है कि काँग्रेस जीएसटी विधेयक में अधिकतम कर की दर को शामिल करवाना चाहती थी, जबकि सरकार का तर्क यह था कि संविधान में कर की दर शामिल करना औचित्यपूर्ण नहीं है। इसके अलावा काँग्रेस की यह भी मांग थी कि प्रस्तावित एक प्रतिशत अतिरिक्त कर हटाया जाना चाहिए। सरकार ने काँग्रेस की दूसरी मांग को स्वीकार कर लिया, जबकि काँग्रेस ने सत्ता पक्ष के तर्क को स्वीकार करते हुए जीएसटी कर की अधिकतम सीमा का अपना आग्रह छोड़ दिया।

क्या है जीएसटी ?

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने राजकोषीय दायित्व और बजट-प्रबंधन (एफआरबीएम अधिनियम) को लागू करने हेतु श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनायी। प्रत्यक्ष करों संबंधी सिफ़ारिशों के अलावा टास्क फोर्स ने केन्द्रीय स्तर पर अप्रत्यक्ष करों, जैसे सेनवेट, सेवा कर इत्यादि के स्थान पर एकल कर यानि वस्तु-सेवा कर लगाने की सिफ़ारिश की। विजय केलकर टास्क फोर्स ने इस सन्दर्भ में बड़ी सौदेबाजी (ग्रैंड बारगेन) का सुझाव दिया, जिसके अनुसार केन्द्र और राज्यों एकसाथ वस्तु सेवा कर लगाने का अधिकार देने की बात की गयी। चूंकि केन्द्र और राज्यों के बीच विभिन्न करों को लगाने के अधिकार का विभाजन हमारे संविधान में दिया गया है, इसलिए इसमें इस प्रकार के बदलाव के लिए संविधान में संशोधन ज़रूरी था, ताकि केन्द्र और राज्यों– दोनों को जीएसटी वसूल पाने का संवैधानिक अधिकार मिले।

जीएसटी लागू होने के बाद केन्द्र और राज्यों के तमाम अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में विलीन हो जायेंगे। केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एवं दवाओं इत्यादि पर उत्पाद-शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा कर (सीवीडी), विशेष सीमा

कर, सरचार्ज एवं सैस इत्यादि केन्द्रीय कर तो उसमें विलीन होंगे ही, साथ-ही-साथ राज्यों द्वारा लागू वैट/बिक्री कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर, लाटरी और जुए पर कर, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जा रहे सैस और प्रवेश-शुल्क समेत तमाम प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में शामिल हो जायेंगे।

राज्यों को यह डर था कि कुछ ऐसे कर हैं, जिनसे उन्हें खासी आमदनी प्राप्त होती है और यदि वे भी प्रस्तावित जीएसटी में विलीन हो जायेंगे तो उनका राजस्व प्रभावित हो सकता है, ऐसे में राज्यों की मांग पर कुछ करों को जीएसटी से अलग रखा गया है, जैसे राज्यों द्वारा लगाया जा रहा आबकारी कर (शराब इत्यादि कर), पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर इत्यादि को जीएसटी की परिधि से बाहर रखा गया है। जीएसटी की खास बात यह है कि अब राज्यों को भी सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार मिल गया है।

क्या हो जीएसटी कर की दर?

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने प्रारंभ में जीएसटी के लिए 27 प्रतिशत की दर का सुझाव दिया था। कुछ समय पहले संस्थान ने पुनराकलन करते हुए यह कहा था कि मानक दर 23 से 25 प्रतिशत के बीच में हो सकती है, जब वस्तुओं को तीन दरों पर कर लगेंगे, जिसमें कुछ विशेष वस्तुओं पर कम कर और अधिकतर वस्तुओं पर मानक दर लागू होगी; और यदि एक ही दर पर जीएसटी लगाया जाता है तो जीएसटी की दर 18 से 19 प्रतिशत हो सकती है। उधर भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकर अरविन्द सुब्रह्मण्यम् ने अधिकतर वस्तुओं पर मानक जीएसटी दर 17 से 18 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया है और जीएसटी के तीन दरों का सुझाव दिया गया है। उनका आवश्यक वस्तुओं पर 12 प्रतिशत, विलासिता के वस्तुओं पर 40 प्रतिशत और शेष वस्तुओं पर 17 से 18 प्रतिशत, सभी सेवाओं पर 17 से 18 प्रतिशत कर का सुझाव है।

ऐसा माना जाता है कि 17 से 18 प्रतिशत से ज्यादा जीएसटी लगाने से सरकार का राजस्व तो बढ़ सकता है, लेकिन यह कदम महंगाई बढ़ानेवाला होगा। यही नहीं, यह अलोकप्रिय कदम होगा। सरकार भी यह नहीं चाहेगी कि जीएसटी प्रारंभ से ही विवादों के घेरे में आ जाए, इसलिए ऐसा लगता है कि सरकार 19 से 20 प्रतिशत जीएसटी लागू करने का प्रयास करेगी।

केन्द्र-राज्य संबंध

जीएसटी लागू करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि राज्य सरकारों को यह डर था कि उन्हें जीएसटी लागू होने से राजस्व की हानि हो सकती है। हालांकि पेट्रोलियम और आबकारी शुल्क को जीएसटी से बाहर रखने से उनकी एक बड़ी शंका तो दूर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें यह डर सता रहा है कि

जीएसटी लागू होने के बाद केन्द्र और राज्यों के तमाम अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में विलीन हो जायेंगे।

दीर्घकाल में उन्हें राजस्व का घाटा होगा, ऐसे में केन्द्र सरकार ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि अगले पाँच साल तक उन्हें होनेवाले राजस्व के नुकसान की भरपाई केन्द्र सरकार करेगी, इसलिए केन्द्र और राज्यों के बीच टकराहट फिलहाल टल गई है।

क्या है फ़ायदा जीएसटी का ?

जीएसटी के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के संबंध में यह तर्क दिया जाता है कि देश में तरह-तरह के अप्रत्यक्ष करों के कारण वस्तुओं की क़ीमत बेज़ा ही बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तरह-तरह के स्तरों पर कर लगने से बार-बार वस्तु पर कर लगता है। उदाहरण के लिए यदि कोई वस्तु उपभोक्ता तक पहुँचने से पहले कई प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरती है, तो हर स्तर पर कर लगाया जाता है। उत्पादक और व्यापारी उपभोक्ता से केवल कर जितनी राशि ही नहीं वसूलते, बल्कि उसपर लाभ भी उपभोक्ता से ही वसूला जाता है। मूल्यवर्धित कर-प्रणाली इस समस्या का समाधान तो है, लेकिन सीमित रूप से, क्योंकि बिक्री-कर, उत्पाद-शुल्क, सेवा कर समेत अलग-अलग प्रकार के कर तो भी लगते ही हैं। जीएसटी-प्रणाली में किसी भी वस्तु पर पहले से दिए गए करों के लिए टैक्स क्रेडिट का प्रावधान होता है, इसलिए सैद्धान्तिक रूप से वस्तु की कीमत केवल उतनी ही बढ़ेगी, जितना उस पर कर लगाया जाता है।

विश्व बैंक ने जीएसटी को एक गेम चेंजिंग आर्थिक सुधार कहा है। माना जाता है कि जीएसटी का सबसे ज्यादा लाभ बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को होगा; क्योंकि वे अपने लेखा-पद्धति (एकाउंटिंग सिस्टम) के कारण विभिन्न करों के विलीन होने का लाभ ज्यादा अच्छी तरह से उठा पायेंगे। इसलिए बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ होते देख विश्व बैंक का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। लेकिन जब हम छोटे उद्योगों की बात सोचते हैं, तो उन्हें फ़ायदा होता नहीं दिख रहा। छोटे उद्योगों को अभी तक 15 करोड़ रुपए तक के उत्पादन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त थी। अब लघु उद्योगों और लघु व्यवसायों पर यह छूट मात्र 25 लाख रखने का प्रस्ताव है। ऐसे में जीएसटी बड़ों को लाभ और छोटों को नुकसान पहुँचानेवाला साबित हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जीएसटी में छोटे उद्योगों को बचाने हेतु उचित संशोधन किए जाएं।

कब होगा जीएसटी लागू ?

हालांकि वित्तमंत्री का कहना है कि 1 अप्रैल, 2017 से जीएसटी लागू हो जायेगा, लेकिन जानकार इस बात से सहमत नहीं हैं। जीएसटी लागू करने के लिए आवश्यक तैयारी हेतु और समय आवश्यक होगा। रिज़र्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने यह कहा है कि 2017 से इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा।

यह सही है कि जीएसटी लागू होने से कर-प्रबंधन में कुशलता आएगी और सरकार को राजस्व का लाभ भी मिलेगा, कर की चोरी भी कम होगी और अकुशल कर-प्रणाली के कारण अनावश्यक रूप से क़ीमतें बढ़ने की प्रवृत्ति भी कम होगी, लेकिन सरकार को ध्यान रखना होगा कि जीएसटी लागू होने के बाद लघु उद्योगों और लघु व्यवसायियों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित हो।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध पीजी डीएवी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।)

एमनेस्टी इंटरनेशनल पर देशद्रोह का मामला दर्ज़

बंगलुरू। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लगे देशविरोधी नारेबाजी की आग अब भी अंदर-ही-अंदर सुलग रही है। इसी का नतीज़ा रहा कि बंगलुरू में भी कुछ छात्रों ने काश्मीर की आज़ादी और भारतीय सेना के खिलाफ नारे लगाये, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने इस गतिविधि का विरोध करते हुए आरोपी युवकों की गिरफ़्तारी की मांग की। इस पर कार्रवाई करते हुए बंगलुरू पुलिस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल और उसके सेमिनार में कथित तौर पर भारत-विरोधी नारे लगानेवालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज़ किया।

बंगलुरू पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त (क़ानून एवं व्यवस्था) चरन रेड्डी ने बताया कि शिकायत के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124 और 154 के तहत मामला दर्ज़ किया गया है। रिपोर्ट में आयोजकों या शामिल लोगों में से किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, लेकिन जांच पूरी करने के बाद इन पर भी कार्रवाई होगी।

विदित हो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा 'ब्रोकन फैमिलीज़' विषय को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें कई काश्मीरी परिवारों को बुलाया गया था। विवाद तब उठा जब कार्यक्रम में इन परिवारों ने कश्मीर में कथित मानवाधिकार-उल्लंघन की बात की और आरोप लगाया कि भारतीय सेना वहाँ के लोगों को तंग करती है। वहीं, चर्चा के दौरान कार्यक्रम में मौजूद काश्मीरी पण्डितों के एक संगठन ने अपनी बात रखी और सेना का समर्थन किया। माहौल तब और गरमा गया जब कथित तौर पर भारतविरोधी और काश्मीर की आज़ादी के नारे लगने लगे। तब वहाँ मौजूद दूसरे संगठन ने 'भारतमाता की जय' के नारे लगाए।

'एमनेस्टी ने नहीं की काश्मीरी पण्डितों के पलायन की बात'

बंगलुरू में 13 अगस्त को एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था के कार्यक्रम में लगाए गए देशविरोधी नारों के खिलाफ अभाविप ने दिल्ली में भी प्रदर्शन किया। कनाट प्लेस-स्थित एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई।

अभाविप के दिल्ली प्रदेश मंत्री भरत खटाना ने बताया कि एमनेस्टी संस्था कार्यक्रमों के माध्यम से हमेशा भारत की ग़लत रिपोर्ट बनाकर विदेशों में पेश करती है। इस संस्था की भारत की शाखा में अधिकतर वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। उन्होंने कहा कि संस्था कहने को तो मानवाधिकारों की बात करती है, लेकिन आजतक इन्होंने काश्मीरी पण्डितों के पलायन की बात नहीं की। इस संस्था ने आतंकवादी और नक्सलवादी हमलों में शहीद होनेवाले लोगों के परिवार के लिए कभी सेमिनार आयोजित नहीं किया।

आत्महत्या की प्रवृत्ति पर आत्ममंथन की ज़रूरत

■ अक्षय दुबे 'साथी'

बीते एक साल में कोटा (राजस्थान) में कोचिंग कर रहे कई विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर हमारे सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है। यह आत्महत्या सिर्फ़ व्यक्तिगत मामले या किसी के द्वारा आनन-फानन में उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि एक लम्बी अवधी से बदल रहे सामाजिक वातावरण और दबावों की उभार का परिणाम है। आख़िर ऐसी क्या विपदा आन पड़ी कि युवाओं को अपनी जीवनलीला समाप्त करनी पड़ रही है? क्या अभिभावकों की उम्मीदों का बोझ युवाओं की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है? या फिर इन युवाओं पर भरोसा करने के बजाय माता-पिता को सामाजिक वर्चस्व की चिंता है जिसके कारण वे अपने बच्चों की समस्याओं को समझने के बजाय उनपर दबाव बनाते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए खोजने आवश्यक हैं।

आत्महत्या की भयावहता के क्रम में कुछ दिन पहले एक विकलांग युवक योगेश साहू ने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह कर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि बेरोज़गारी से परेशान विकलांग युवक को मुख्यमंत्री के जनदर्शन में जाने से रोका गया था। वह मुख्यमंत्री से रोज़गार और अपनी बहन के विवाह के लिए सहयोग की अर्ज़ी लगाना चाह रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री-जनदर्शन में जाने से उसे रोके जाने पर क्षुब्ध होकर युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर खुद पर आग लगा ली।

एक तरफ जहाँ युवक के द्वारा आत्महत्या के लिए कदम उठाना बेरोज़गारी की मार और शासन के प्रति रोष की पराकाष्ठा को प्रकट करता दिखाई देता है, वहीं किसान-आत्महत्या, परीक्षा में ज्यादा अंकों का दबाव या पारिवारिक कलह से परेशान होकर मौत को गले लगाने की बढ़ती प्रवृत्ति हमारे समाज के लिए एक गंभीर सवाल भी छोड़ रही है। भारत के लिए यह समस्या इसलिए भी एक चुनौती है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में सर्वाधिक आत्महत्याएँ भारत में हो रही हैं। 'प्रीवेटिंग स्यूसाइड' नाम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2012 तक 2,58,075 लोगों ने आत्महत्या की। जबकि दुनियाभर में हर साल लगभग आठ लाख लोग अपनी जान ले लेते हैं।

आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में वरिष्ठ पत्रकार अजीत सिंह कहते हैं कि 'आत्महत्या-जैसा कदम गंभीर मानसिक पीड़ा की हालात को व्यक्त करता है। इसे किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता लेकिन इसके कारणों को समझना ज़रूरी है।' अजीत सिंह की मानें तो युवाओं में बेरोज़गारी, विकल्पहीनता, अर्थव्यवस्था की सामाजिक असुरक्षा ही आत्महत्या-जैसी सोच को जन्म देती है। इसे व्यक्तिगत मामले या हादसे समझकर नज़रअंदाज़ करना उचित नहीं। इन बातों को आँकड़ों से भी समझा जा सकता है क्योंकि

सन 2012 के आँकड़े बताते हैं कि 75 प्रतिशत आत्महत्या के मामले मध्यम और कम आयवाले देशों में हुए हैं। वहीं, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी आत्महत्या की घटनाओं के लिए सीधे तौर पर सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर मामलों में बेरोज़गारी ही मुख्य वज़ह होती है, जो दर्शाती है कि शासन-प्रशासन की नाकामी से हारकर युवाओं ने उक्त कदम उठाये।

जबकि, गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर के सामाजिक विज्ञान संकाय की डीन डॉ. अनुपमा सक्सेना इसके लिए मुख्य कारक 'असहायता-बोध' मानती हैं। उनका कहना है कि विकल्पहीनता से ज़्यादा यह मुद्दा विकल्पों को न प्राप्त कर पाने की असहायता के बोध का है। वे आगे कहती हैं, 'कोई अचानक आत्महत्या नहीं करता। अपने दुःख-दर्द को लेकर व्यक्ति सब जगह घूमता है पर जब हार जाता है तब यह कदम उठाता है।' आत्महत्या की समस्या के निदान पर जोर देते हुए डॉ. अनुपमा सक्सेना कहती हैं कि जितना ध्यान एक व्यक्ति के मर जाने के बाद उसकी समस्याओं और ज़रूरतों पर सरकार और समाज देती है, उतना ही यदि जीवित भटकने पर दे दिया जाए तो ऐसी घटनाएँ निश्चित तौर पर कम हो जाएंगी।

हमारे देश में पिछले दो दशकों में आत्महत्या के मामलों में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड्स ब्यूरो के अनुसार आज भारत में 37.8 फीसदी आत्महत्या करनेवाले लोग 30 वर्ष से भी कम उम्र के हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, हर खुदकुशी की वजह अलग-अलग होती है। किसान की खुदकुशी, छात्रों की खुदकुशी या फिर अपराधबोध होने पर आत्महत्या की स्थितियों को एक ही पलड़े में नहीं रखा जा सकता। तीनों के किरदार अलग-अलग हैं। हम लोग सरलीकरण के आदी हैं, इसलिए हर चीज का दोष सरकार पर डाल देते हैं, यह जानते हुए भी कि राज्य अब कल्याणकारी नहीं रह गया है।

मगर सवाल अब भी यहीं कि आख़िर क्यों युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति इतनी बलवती हो रही है। ऐसे में राजस्थान में अध्ययन के लिए आई कृति के सुसाइड नोट की पंक्तियाँ भी हमारे सामने कई सवाल छोड़ती हैं। कृति ने सुसाइड नोट में लिखा, 'वह क्यों मर रही है और क्यों मर रहे हैं यहाँ के बच्चे ! मैं भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से कहना चाहती हूँ कि यदि वे चाहते हैं कि कोई बच्चा न मरे तो जितनी जल्दी हो सके इन कोचिंग संस्थानों को बंद करवा दें। ये कोचिंग छात्रों को खोखला कर देते हैं। पढ़ने का इतना दबाव होता है कि बच्चे बोझतले दब जाते हैं।' यह सिर्फ कृति के शब्द नहीं हैं बल्कि उन सभी युवाओं के भी शब्द कुछ ऐसे ही होंगे, जो ज्यादा दबाव की स्थिति में खुद को संभाल नहीं पाते। ऐसे में ज़रूरी है यह समझना कि दबाव बनाने से कोई हल नहीं निकलता। साथ ही युवाओं को भी समझाने की ज़रूरत है कि दबाव में बिखरने से बेहतर उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करना है। ■

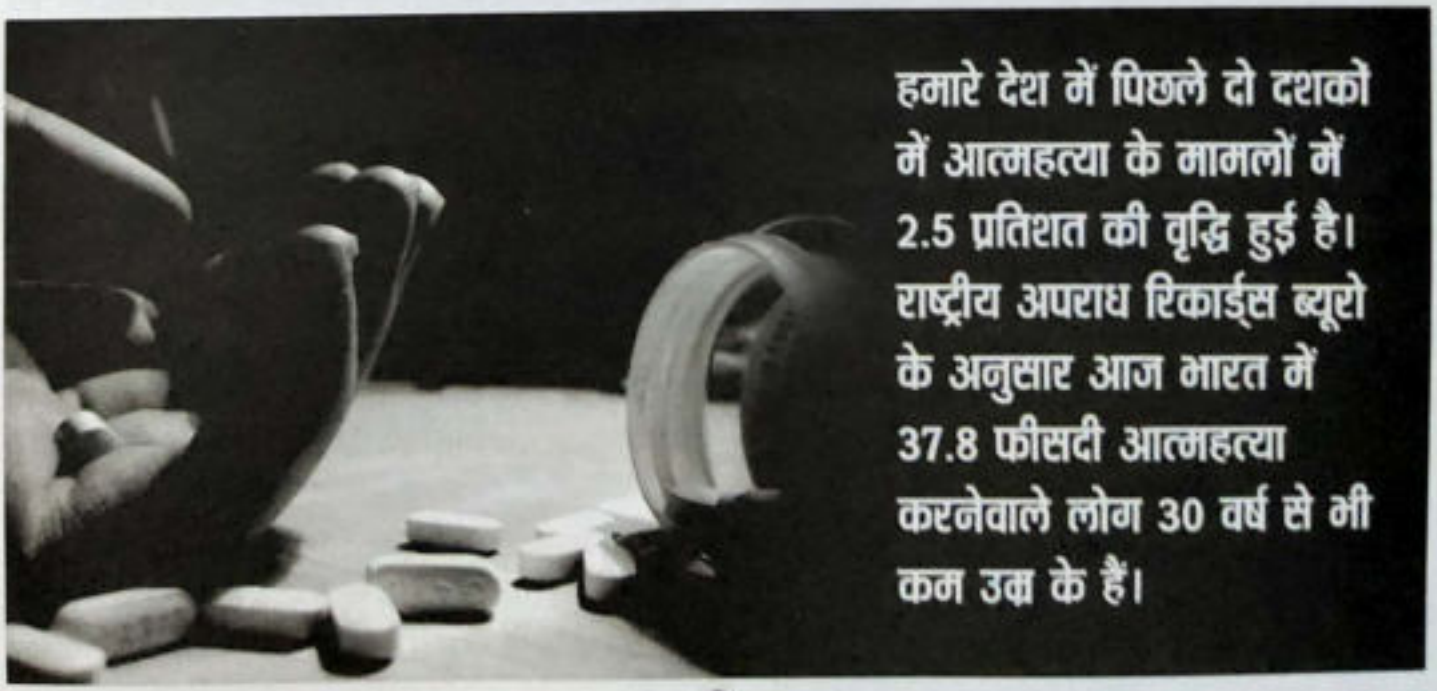

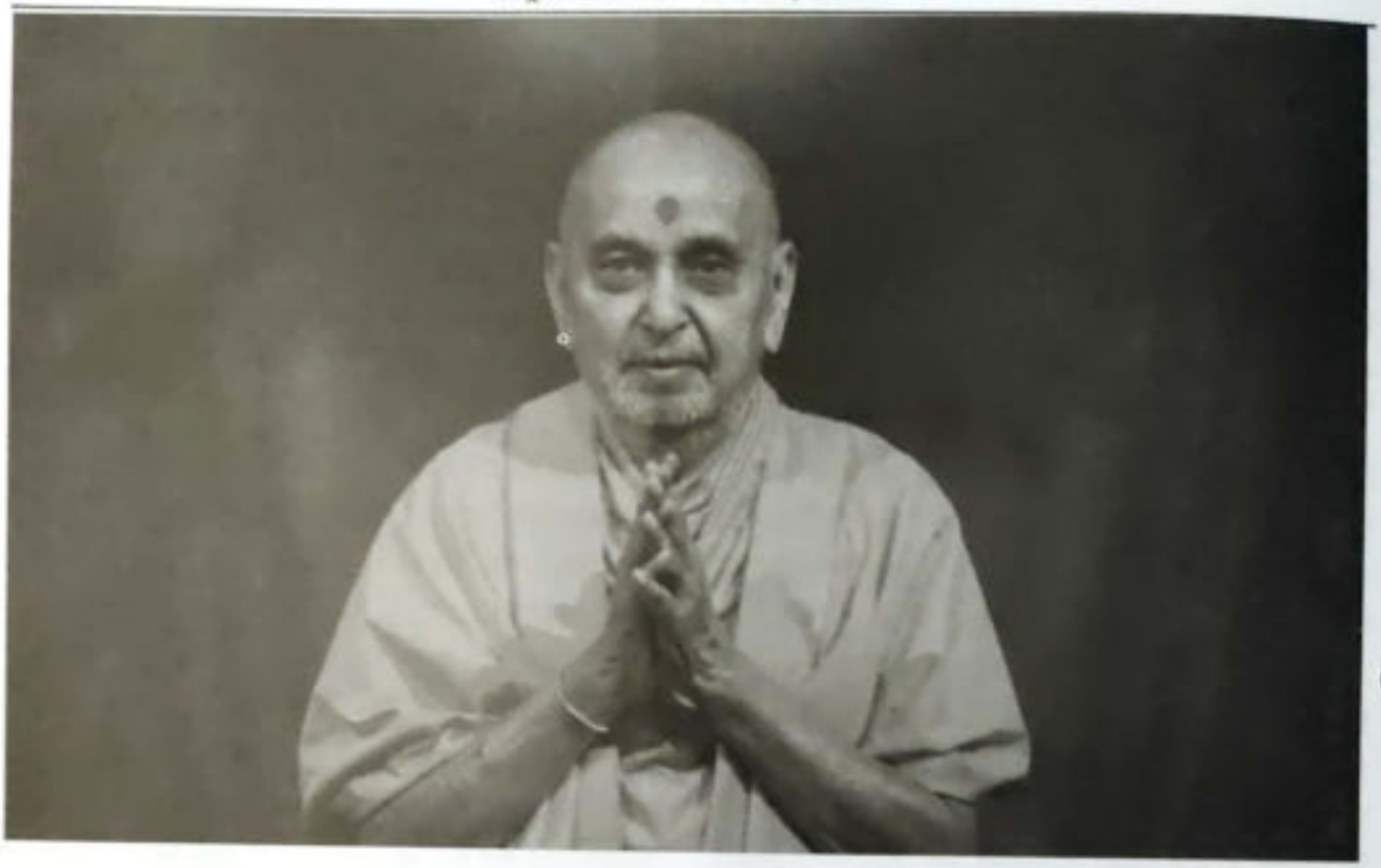

प्रमुख स्वामी ने रचा वैदिक मूल्यों पर आधारित आस्था का माहौल

देश-दुनिया में अक्षरधाम मन्दिरों की संचालक और स्वामीनारायण संप्रदाय की बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था (बीपीएएस) के प्रमुख स्वामी का गत 13 अगस्त को बोटाद के सारंगपुर में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रमुख स्वामी ने अपने 65 वर्ष के कार्यकाल में देश-विदेश के 70 हज़ार से अधिक गाँव व शहरों का भ्रमण कर 1,100 मन्दिरों निर्माण कराया। नशामुक्ति व संस्कार-सींचन के लिए 9,090 संस्कार-केन्द्र व 55,000 स्वयंसेवक तैयार किए जो भूकंप, अकाल, सूखा व अन्य आपदा में लोगों की मदद करने पहुँचते हैं।

सात दिसंबर, 1922 को जन्मे प्रमुख स्वामी महाराज ने 18 साल की उम्र में गृह त्यागकर वैराग्य का मार्ग चुना था। इनका असली नाम शान्तिलाल पटेल है। प्रमुख स्वामी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वामी केशवजीवन दास महाराज को चुना। वर्ष 2012 में ही उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का नाम लिफाफे में लिखकर रख दिया था।

स्वामी जी को याद करते हुए डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने लिखा था कि राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। उन पर दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का दबाव था, तब उन्होंने प्रमुख स्वामी को अमेरिका फोन लगाकर पूछा था कि क्या उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहिए। तब प्रमुख स्वामी ने उन्हें मना कर दिया था। स्वामी जी के साथ अपनी मंत्रणा को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम ने अपनी किताब **'ट्रांसेंडंस माय स्पिरच्युअल एक्सपीरियंस विथ प्रमुख स्वामीजी'** में लिखा है।

डॉ. कलाम ने इस किताब में लिखा : 'प्रमुख स्वामी ने मुझसे कहा था कि निःस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करो। यह पद अन्य किसी उच्च पद से भी बड़ा है। इससे भी मानव महान् बन सकता

है। उनकी इस सलाह के बाद मैंने अपने दो बैग में सामान रखा और राष्ट्रपति भवन को अलविदा कह दिया। उस समय मैंने महसूस किया कि मैं स्वच्छंद विचरनेवाला साधु हूँ।' कलाम की किताब 'ट्रांसेंडंस माय स्पिरच्युअल एक्सपीरियंस विथ प्रमुख स्वामीजी' के हरेक पन्ने पर प्रमुख स्वामी के प्रति उनकी भक्ति छलकती है। डॉ. कलाम के शब्दों में स्वामी जी ने वैदिक मूल्यों के आधार पर विश्वभर में आस्था का माहौल बनाया।

डॉ. कलाम ने प्रमुख स्वामी के साथ अनेक आध्यात्मिक और चमत्कारिक अनुभव लिए। 30 जून, 2001 को डॉ. कलाम पहली बार प्रमुख स्वामी से मिले थे। इस दौरान उन्होंने एक घंटे तक प्रमुख स्वामी से अनेक विषयों पर चर्चा की थी। उसी क्षण से वे स्वामीजी के भक्त बन गए थे। प्रमुख स्वामी की तबीयत नाजुक होने की ख़बर डॉ. कलाम को लगी, तो वे 11 मार्च, 2014 को सारंगपुर पहुंचे थे।

डॉ. कलाम लिखते हैं कि 'किसी अलौकिक दिव्यता के बीच स्वामीजी ने दस मिनट तक मेरे हाथों को पकड़कर रखा। हमारे बीच एक शब्द की भी बातचीत नहीं हुई। उस समय हमारे बीच मौन संवाद चल रहा था। यह एक अद्‌भुत आध्यात्मिक अनुभव था।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रमुख स्वामी के अंतिम दर्शन के दौरान तथा बाद में संतों को अपने संबोधन के दौरान बेहद भावुक और रूंआसे हो गये। उन्होंने कहा कि बहुत-से लोगों ने अपने गुरु को खोया है, पर उन्होंने एक पिता को खो दिया। मोदी लाल किले पर ध्वजारोहण और संबोधन के बाद विशेष विमान से अहमदाबाद पहुँचे और वहाँ से हैलीकॉप्टर के जरिये सारंगपुर आये। मोदी ने अपने भाषण के दौरान दिवंगत संत के साथ अपनी कई पुरानी यादों को भी साझा किया और खुलासा किया कि वह गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके भाषणों का वीडियो देखकर उनमें गलतियों को सुधारने की उन्हें सीख भी देते थे।

मोदी ने कहा कि संत-परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत का आधुनिक भारत के अनुरूप संस्थाकरण करनेवाले प्रमुख स्वामी संतों को हर प्रकार की जानकारी से लैस करने के पक्षधर थे। वह एक आदर्श गुरु के साथ ही एक आदर्श शिष्य भी थे। वह संत होने के साथ ही साथ लोगों के बड़े पारखी भी थे। उनका प्रभाव दिवंगत डॉ. अब्दुल कलाम के भारत के विजन 2020 पर भी दिखता है। ■

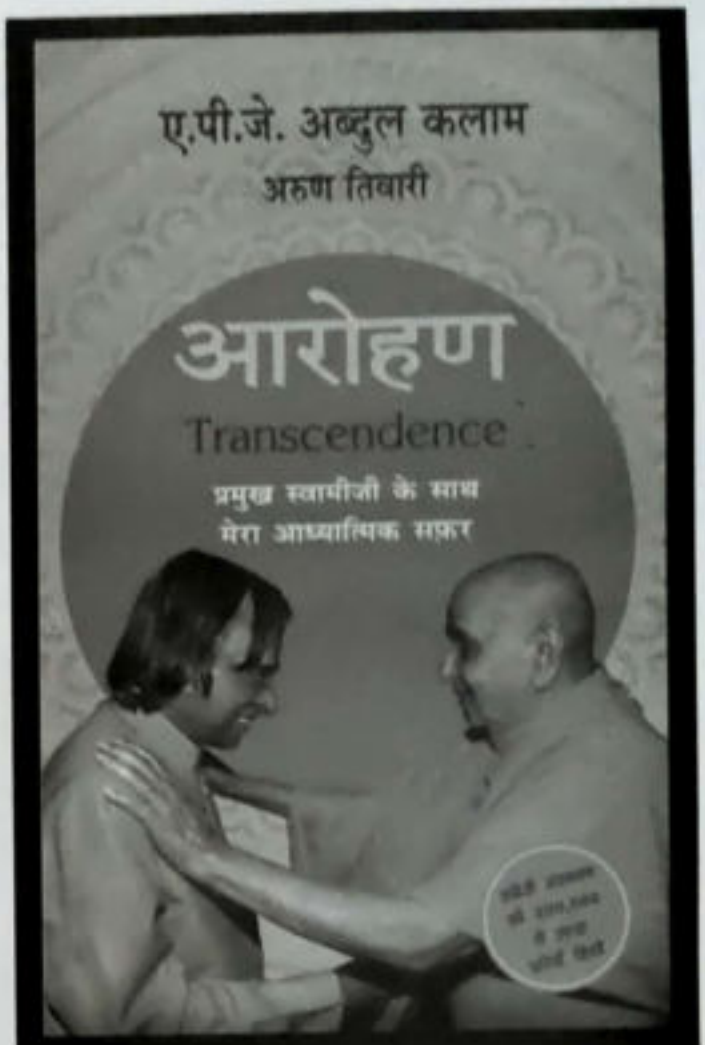

डॉ. कलाम ने 'ट्रांसेंडंस माय स्पिरच्युअल एक्सपीरियंस विथ प्रमुख स्वामीजी' नामक पुस्तक में लिखा है : 'प्रमुख स्वामी ने मुझसे कहा था कि निःस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करो। यह पद अन्य किसी उच्च पद से भी बड़ा है। इससे ही मानव महान् बन सकता है। उनकी इस सलाह के बाद मैंने अपने दो बैग में सामान रखा और राष्ट्रपति भवन को अलविदा कह दिया। उस समय मैंने महसूस किया कि मैं स्वच्छंद विचरनेवाला साधु हूँ।'

"छात्राओं में नेतृत्व-क्षमता बढ़ाना ही अभाविप का लक्ष्य"

चित्तौड़गढ़। 'आज पूरी दुनिया नारी शक्ति का लोहा मान चुकी है। बदलते युग के साथ हमें भी अपने-आप में बदलाव लाना होगा। अपने हक़ की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् लगातार प्रयास कर रही है कि छात्राएँ आगे आकर नेतृत्व को स्वीकारें। छात्राओं में नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाना अभाविप के प्रमुख कार्यों में से एक है। छात्रा-शक्ति बदलाव ला सकती है। आज भी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म होता है, केवल नाम बदल जाते हैं। नारी हर क्षेत्र में आगे है। भारतीय संस्कृति कहती है यहाँ रहनेवाले सभी समान हैं। बालक-बालिका में भेद कतई नहीं होना चाहिए। परीक्षाओं में लड़कियाँ बाजी मारती हैं। रक्षाबंधन पर भाई बहनों को ढूँढ़ते हैं। पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता। नवरात्रि में कन्या-भोजन सबसे पुण्य माना जाता है तो फिर नारी अपने आप को क्यों कमजोर आँकती है?' उक्त बातें अभाविप की अखिल भारतीय छात्रा प्रमुख ममता यादव ने चित्तौड़गढ़ में आयोजित छात्रा सम्मेलन में छात्राओं को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ वीरों की धरती है जिसे मीरा की भक्ति, पद्मिनी के जौहर व पन्ना धाय के त्याग व बलिदान के लिए हमेशा याद किया जाता है। ऐसी भूमि पर छात्रा सम्मेलन का आयोजन बेटियों के बढ़ते कदम को ऐतिहासिक बदलाव का संकेत दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमें कमियों को सुधार कर फिर से वैदिक युग लाना है। वर्तमान समय में शिक्षा की वास्तविक स्थिति क्या है, इस पर चिन्तन करना है। वर्तमान परिस्थितियों में छात्राओं को स्वप्रेरणा से हर लड़ाई लड़नी होगी तभी जाकर सामाजिक ढाँचे में बदलाव दिखेगा। इस हेतु सभी छात्राओं को समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

इस अवसर पर प्रदेश सह-संगठन मंत्री राजेश गुर्जर ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान में वीरों की नगरी में ऐसा विशाल छात्रा सम्मेलन छात्राओं को अपने सामर्थ्य एवं स्वालंबन से हर कार्य को करने की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि परिवार, घर, समाज और देश– सभी के निर्माण में महिला वर्ग की भूमिका खास होती है। ऐसे में जो छात्राएँ आज समाज और देश के गौरव के लिए अपना जीवन समर्पण करती हैं, वहीं बेहतर भविष्य की बुनियाद रख पाती हैं।

सम्मेलन के पश्चात् विद्यार्थी परिषद् की छात्राओं द्वारा द्वारिकाधाम से कलेक्ट्रेट परिसर तक विशाल रैली भी निकाली गई। एक हज़ार से अधिक की संख्या में छात्राओं ने हाथों में 'फूल भी हैं, चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं' लिखी तख्तियाँ लिए पैदल मार्च किया। कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए 11-सूत्रीय मांगों को लेकर ज़िला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया।

ज्ञापन में कहा गया है कि ज़िले में करीब 10 हजार छात्राएँ हैं, लेकिन छात्राओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुरक्षा एवं सम्मान के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए नगर में महिला पुलिस अधिकारी स्वतंत्र प्रभार के रूप में नियुक्त हो, गर्ल्स कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे लगवाएँ तथा इसे पीजी के क्रमोन्नत किया जाए, छात्राओं को त्वरित न्याय के लिए स्थानीय स्तर पर कानून बनाया जाए एवं फास्ट ट्रैक छात्रा अदालत खोले जायें।

परिचर्चा

छात्र संघ-चुनाव

धनबल, बाहुबल और सत्ताबल की राजनीति

छात्र संघ का बिगुल बज चुका है। देशभर के विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में छात्रसंघ-चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में छात्र संघ-चुनाव एक उत्सव की भाँति मनाया जाता है। चुनाव के तीन-चार महीने पहले से ही भावी प्रत्याशी अपने-अपने ढंग से छात्रों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। कैम्पस में ईमानदार, साफ़-सुथरी छविवाला व कुशल नेतृत्वकर्ता बनने की होड़-सी लग जाती है। साम, दाम, दण्ड, भेद– हर प्रकार से कैम्पस में यह दिखाने की कोशिश होती है कि उनसे (भावी प्रत्याशियों से) ज्यादा कैम्पस के विकास के लिए समर्पित कोई और नहीं है। शिक्षा-व्यवस्था में सुधार, कक्षाएँ नियमित चलवाने का आश्वासन, पुस्तकालय, छात्रावास की सुविधा व छात्राओं की सुरक्षा-जैसे मुद्दों को लेकर छात्रनेता राजनीति की प्रथम पाठशाला में उतरते हैं।

छात्र संघ-चुनाव से जहाँ एक ओर परिवारवाद, क्षेत्रवाद व जातिवाद को दूर करने में किसी हद तक सफलता मिली है वहीं दूसरी ओर धनबल, बाहुबल और सत्ताबल की राजनीति के चलते छात्र संघ की गरिमा भी कलंकित हुई है। गाड़ियों का लम्बा काफ़िला, पार्टियों का आयोजन, लाखों रुपये के पोस्टर-बैनर और करोड़ों रुपये बहाकर चुनाव लड़नेवाले छात्र सामान्य तो नहीं हो सकते? छात्र राजनीति का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का निवारण करना है और साथ ही एक ऐसा नेतृत्व भी तैयार करना है जिससे छात्र समाज की समस्याओं का निवारण करने में स्वयं सक्षम हो सके। परन्तु आज की हिंसक राजनीति ने आम छात्र को चुनाव से दूर कर दिया है। छात्र संघ-चुनाव की वर्तमान स्थिति पर राष्ट्रीय छात्रशक्ति के लिए उत्कर्ष श्रीवास्तव ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं से बातचीत की।

समय के साथ छात्र संघ-चुनाव में भी परिवर्तन दिखाई दिया है। उनमें कुछ सकारात्मक रहे, जैस– चुनाव में पहले से अधिक पारदर्शिता, छात्र संघ में छात्राओं की बढ़ती भागीदारी, लिंगदोह समिति के नियम आदि। परन्तु नकारात्मक परिवर्तन की संख्या भी काफ़ी रही। पहले छात्र संघ चुनाव छात्रहित के मुद्दों पर लड़े जाते थे। छात्र वर्षभर छात्रों की समस्याओं के लिए जूझते थे और विश्वविद्यालय या महाविद्यालय-परिसर में शैक्षिक वातावरण हो, इसके लिए सभी संगठनों के छात्रनेता एकमत रहते थे। लेकिन आज छात्रहितों की बात कोई नहीं करता और शैक्षिक समस्याओं से किसी प्रत्याशी का लेना-देना नहीं होता। आज कैम्पसों में सीधे राष्ट्रीय राजनीति की बात होती है और कैम्पस में राजनीतिक पार्टियों की उपलब्धि गिनवाकर वोट मांगा जाता है। कुल मिलाकर बाहुबल, सत्ताबल और धनबल के जरिये चुनाव लड़नेवाले नेता, जिन्हें नेता कहना भी गलत है, आज शिक्षा और समाज के स्तर को ऊँचा उठाने की बात कर चुनाव लड़ते हैं। आज कैम्पस का छात्र संघ चुनाव छात्रहितों के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए लड़ा जाता है। —**नलिनी मिश्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय**

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव अन्य सभी विश्वविद्यालयों के छात्रसंघ चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ धनबल, बाहुबल और सत्ताबल का प्रयोग भी जमकर होता है। ओपन कैम्पस होने के कारण चालीस से अधिक कैम्पसों में चुनाव-प्रचार करना होता है। वैसे कैम्पस तो दिल्ली में ही स्थित है, परन्तु परिसरों की दूरी भी मामूली नहीं है इसलिए यहाँ प्रचार का तरीका भी भिन्न है, जिससे यहाँ पैसे और रसूख की तूती बोलती है। दिल्ली विवि का छात्रसंघ चुनाव आम छात्रों का न होकर वर्ग (गुट) विशेष का होता है। किसको चुनाव में खड़ा करना है और कौन प्रत्याशियों पर खर्च करेगा, यह फ़ैसला समाज विशेष के लोगों द्वारा बैठकों में तय किया जाता है। सच तो यह है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित छात्रसंघ का तमगा होने के बावजूद दिल्ली छात्रसंघ चुनाव में छात्रहितों के मुद्दे गौण रहते हैं और चुनाव लड़ने का केन्द्र पैसे व ताकत का प्रदर्शन होता है। लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्याशी को मात्र 5 हजार रुपये में चुनाव लड़ना होता है लेकिन करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। प्रत्याशियों के प्रचार में नेता, अभिनेता व समाज के प्रतिष्ठित लोग भी अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। **–राहुल ओझा, दिल्ली विश्वविद्यालय**

छात्र-राजनीति, विश्वविद्यालय शिक्षण-व्यवस्था का अहम घटक रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदनमोहन मालवीय जी ने 'छात्र और राजनीति' नामक लेख में लिखा था कि जब तक राष्ट्र पर कोई बड़ा संकट न हो, तब तक छात्रों को राजनीति से दूरी बनाए रखनी चाहिए। उन्हें अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केन्द्रित करना चाहिए ताकि वे एक बुद्धिजीवी नागरिक बन सकें और देश की उन्नति में ज्यादा बेहतर योगदान दे सकें। एक समय था जब युवा सकारात्मक राजनीति की दिशा में अग्रसर थे, लेकिन यह विडम्बना ही है कि पिछले 20-25 वर्षों मे छात्र राजनीति में धनबल, बाहुबल और आपराधिक प्रवृत्तियों की बाढ़-सी आ गई है। छात्रसंघ में आज आम छात्र पूरी तरह कट-सा गया है और आपराधिक छविवाले लोग पूरी तरह अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं। लिंगदोह कमेटी की संस्तुतियों का असर पूरी तरह बेअसर हो गया है। छात्र-राजनीति के लिए यह ज़रूरी है कि छात्रसंघों के चुनाव हों और उसमें से छात्र चुनकर आयें। जिन सिद्धान्तों पर छात्रसंघ की आधारशिला रखी गई थी, उन सिद्धान्तों की कसौटी पर कोई चलने की कोशिश नहीं कर रहा है।

–आयुषी श्रीमाली, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छात्रसंघ चुनाव करीब है। ऐसे में चुनाव-प्रचार के लिए पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। शहर की दीवारें व अन्य खाली स्थान पोस्टर-बैनरों से भर दिए गए हैं। बाहर से बुलाए गए किराये के लड़कों को कैम्पस में चुनावी पम्फ्लैट बाँटते हुए देखा जा सकता है। जल्द ही हॉस्टलों और किराये पर रहनेवाले छात्रों को मुफ़्त भोजन, फ़िल्में और पिकनिक पर ले जाने का क्रम भी शुरू होगा। छात्रों को अपने कैम्पस के फुटपाथ और सीढ़ियाँ नज़र आनी बन्द हो जायेंगी और हर जगह किसी के नाम की हैण्डबिल नज़र आने लगेगी। भारी मात्रा में कागज़ की बर्बादी के साथ ही कैम्पस में तेज गाड़ियों के काफ़िले और किराये के लड़कों द्वारा अपने प्रत्याशी के समर्थन में नारेबाजी की आवाज़ सुनाई देगी। यह सब दिल्ली छात्रसंघ चुनाव की कुछ झलकियाँ मात्र है जो खुलेआम लिंगदोह की संस्तुतियों का विरोध करती है।

–विजय यादव, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

राजनीतिक पार्टियाँ स्वार्थवश छात्र संघ-चुनाव में अपनी दखल देती हैं, जिसके कारण धनबल और बाहुबल की राजनीति बढ़ती जा रही है। राजनीतिक पार्टियों को अपना वोट बैंक छात्र संघ-चुनाव से ही नज़र आने लगता है और राजनीतिक दल छात्र संघ-चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं। राजनीतिक सरपरस्ती का ही नतीजा है कि खुलेआम लिंगदोह कमेटी की धज्जियाँ उड़ानेवाले छात्रनेता कैम्पस की शुचिता के लिए संघर्षरत दिखाई देते हैं। बाहर से आए हुए तथाकथित छात्रनेता, जो किसी गुट विशेष या पार्टी-विशेष द्वारा प्रायोजित होते हैं, पैसे व गुण्डागर्दी के दम पर चुनाव लड़ते हैं। रसूख और पैसों के दम पर वे कुछ दिनों में ही वे कैम्पस का सबसे चर्चित चेहरा बन जाते हैं। इसी स्थिति के कारण सामान्य छात्र कॉलेज़ राजनीति से दूरी बना रहे हैं।

–अम्बेश सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

छात्र-राजनीति में राजनीतिक दलों की दख़ल बढ़ने से शैक्षिक अराजकता का माहौल कायम हो गया है। आजकल स्थिति यह रहती है कि विश्वविद्यालय के हर छोटे-से-छोटे कार्यक्रम में राजनीतिक दल के व्यक्तियों को बुलाया जाता है। छात्र संघ से चुने गए छात्रनेता शिक्षकों का खुलेआम अपमान करते हैं क्योंकि वे छात्र कम, गुण्डे अधिक नज़र आते हैं। धनबल की राजनीति ने छात्र संघ-चुनाव को भी लोकसभा और विधानसभा-जैसा बना दिया है। आज छात्र संघ चुनाव में किसी बड़े मठाधीश के समर्थन के बिना उतरना मुमकिन नहीं है क्योंकि पहले तो आम छात्र को पैसे के दम पर चुनाव लड़ने से रोका जाता है और यदि फिर भी वह नहीं मानता तो बाहुबल अर्थात् गुण्डागर्दी के दम पर उसे बैठा दिया जाता है। चुनाव के गिरते स्तर का कारण भी परिसर में गुण्डागर्दी और अराजकता है।

–विशाल राणा, दिल्ली विश्वविद्यालय

रंग लाया अभाविप का संघर्ष, फीस-बढ़ोत्तरी का फ़ैसला वापस

चंडीगढ़। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने अपने संघर्ष से एक बार फिर छात्रों की समस्याओं का निस्तारण किया है। इस बार मामला पंजाब विश्वविद्यालय का है जहाँ कैंपस-प्रशासन ने फ़ीस-बढ़ोत्तरी का फ़ैसला लिया था, जिसके विरोध में अभाविप-कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल की। लोकतांत्रित तरीके से विश्वविद्यालय-प्रशासन के ग़लत फ़ैसले के ख़िलाफ़ खड़ी रही अभाविप के सामने आख़िरकार प्रशासन को झुकना पड़ा और फ़ीस-बढ़ोत्तरी का फ़ैसला वापस ले लिया गया।

इस दौरान, डीएसडब्ल्यू प्रो. नवदीप गोयल ने कुलपति-दफ़्तर के सामने भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को जूस पिलाकर अनशन ख़त्म करवाया। प्रो. गोयल ने कहा कि ट्यूशन फ़ीस में इस वर्ष कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। वहीं, अभाविप छात्र नेता गगन चौधरी ने बताया कि पीयू प्रशासन ने छात्रों की सभी मांगों को मान लिया है। चौधरी के अनुसार डीएसडब्ल्यू प्रो. नवदीप ने यह भी आश्वासन दिया है कि 30 सितंबर तक परीक्षा फ़ीस में भी बढ़ोतरी नहीं होगी।

ग़ौरतलब है कि पंजाब विश्वविद्यालय प्रशासन ने 22 जुलाई को सिंडीकेट और 24 जुलाई को सीनेट में 2016-17 के लिए परीक्षा-फ़ीस में 35 फीसदी तक बढ़ोत्तरी का फ़ैसला लिया था। फ़ीस-बढ़ोत्तरी को लेकर सभी छात्र संगठनों ने पीयू-प्रशासन के ख़िलाफ़ जमकर विरोध किया था।

प्राचीन धरोहरों का संरक्षण ही विकासार्थ विद्यार्थी का उद्देश्य : सचिन दवे

'प्राचीन धरोहरों को खत्म करके कभी विकास नहीं हो सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके ही विकास किया जा सकता है। पर्यावरण-असंतुलन का मुख्य कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन है। दिन-प्रतिदिन पर्यावरण-असंतुलन बढ़ता जा रहा है। असामयिक वर्षा, अम्ल-वर्षा, वज्रपात आदि घटनाएँ पर्यावरण-असंतुलन का ही परिणाम हैं। अगर समय रहते नहीं चेते, तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रह जायेगा। विकास होना अच्छी बात है, लेकिन प्रकृति को अनदेखा करते हुए कदापि संभव नहीं है। 'विकासार्थ विद्यार्थी' अपने स्थापना-काल से ही लोगों में प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। प्राचीन धरोहरों को बचाना ही 'विकासार्थ विद्यार्थी' (एसएफडी) का उद्देश्य है।' उक्त बातें अभाविप के 'विकासार्थ विद्यार्थी' आयाम के राष्ट्रीय संयोजक सचिन दवे ने विकासार्थ विद्यार्थी द्वारा कपूरथला में आयोजित दो-दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला में कही।

इस अवसर पर रासायनिक कृषि के दुष्परिणाम के बारे में विस्तार से बताते हुए कृषि-विशेषज्ञ उमेन्द्र दत्त ने कहा कि जो रासायनिक खाद प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उससे खेती योग्य भूमि बंजर होते जा रही है। जैविक कृषि के अनेक फ़ायदे हैं। जैविक खेती के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए।

मैली हो चुकी कालीबेई नदी को साफ़ करनेवाले संत बलवीर सिंह सींचेवाल ने बताया कि शुरू-शुरू में मुझे भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, परंतु निरंतर प्रयास से अब कालीबेई नदी साफ़ दिखने लगी है। इस नदी को साफ़ करने के लिए भावी प्रोजेक्ट के बारे में भी वहाँ उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया। विदित हो कि गुरु नानक देव को ज्ञान की प्राप्ति कालीबेई नदी के पास ही हुई थी।

इसी क्रम में उन्होंने अपने सींचेवाल ग्राम का उल्लेख करते हुए कहा कि सींचेवाल ग्राम में वाटर ट्रिटमेंट प्लांट, पानी की समुचित सुविधा, छात्रों को पढ़ने के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त विद्यालय मौजूद है। इस गाँव में लोगों के स्वरोज़गार हेतु तकनीकी कार्य सिखाए जाते हैं। कालीबेई नदी की सफ़ाई और सींचेवाल ग्राम की विशेषता को सुनकर कार्यशाला में उपस्थित प्रतिनिधि उनसे काफ़ी प्रेरित हुए।

दूसरे दिन के छठे सत्र में जम्मू, हरियाणा, पंजाब व हिमाचलप्रदेश में 'विकासार्थ विद्यार्थी' द्वारा किए गए कार्यों के बारे में रिपोर्ट पेश किया गया तथा आगामी योजनाओं की रूपरेखा के बारे में चर्चा की गयी।

समापन-सत्र के बाद सभी प्रतिनिधियों ने संत बलबीर सिंह सीचेवाल द्वारा साफ़ की गई कालीबई नदी को देखा और संत सीचेवाल के गाँव का भ्रमण भी किया। सींचेवाल ग्राम भ्रमण के दौरान वहाँ की साफ़-सफ़ाई व मौजूद सुविधाओं को देखकर कार्यकर्ता काफ़ी अभिभूत हुए और कहा कि बग़ैर सरकारी मदद के संत सीचेवाल जी ने जो कर दिखाया है, वह अनुकरणीय है। ■

पर्यावरण-संरक्षण पर 'विकासार्थ विद्यार्थी' द्वारा कार्यशाला आयोजित

पर्यावरण-संरक्षण को लेकर लोगों मे जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के आयाम 'विकासार्थ विद्यार्थी' द्वारा चाम्पा (छत्तीसगढ़) में दो-दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी। इस कार्यशाला में विकासार्थ विद्यार्थी के इतिहास और विकास के बारे में बताते हुए विकासार्थ विद्यार्थी के राष्ट्रीय संयोजक सचिन दवे ने कहा कि इसकी विधिवत् स्थापना 1992-93 में की गई। एसएफडी की राष्ट्रीय कार्यशाला बंगलुरू और मुम्बई में आयोजित कराई जा चुकी है। इसके कार्यों की शुरूआत आईआईटी मुम्बई से हुई। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण और प्राचीन धरोहरों को संरक्षित करना है। स्मार्ट सिटी के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण ज़रूरी है। तालाब और कुएँ के बिना स्मार्ट सिटी संभव नहीं है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। सोलर कैंपस से ही सुपर कैंपस का निर्माण होगा।

पिछले वर्षों में विद्यार्थी विकासार्थ, छत्तीसगढ़ द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रांत संयोजक उत्कर्ष त्रिवेदी ने बताया कि पिछले एक वर्ष में हमलोगों ने ग्रीन कैंपस-क्लीन कैंपस को लेकर जागरुकता-अभियान चलाया। कवर्धा में दूध नदी की सफ़ाई, पक्षियों के सकोरे की व्यवस्था, रायपुर में तालाब और मन्दिरों में सफ़ाई-कार्य, ट्रैफिक कर्मियों पानी-पाउच वितरण आदि किया।

बाद में नर्मदा नदी का वृत्तचित्र दिखाया गया और बताया गया कि किस तरह मैली हो चुकी नर्मदा नदी को विद्यार्थी परिषद् के द्वारा बचाया गया। पूरे 21 दिन के भ्रमण-अभियान के बाद विद्यार्थी परिषद् के लगभग 50 कार्यकर्ताओं ने मिलकर नर्मदा नदी में हो रहे प्रदूषण की जानकारी सरकार एवं अन्य संस्थाओं को दी जिसके बाद सरकार के द्वारा लगभग 1,100 करोड़ रुपये नर्मदा बचाओ अभियान के लिए दिए गए।

विगत वर्ष विद्यार्थी विकासार्थ द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा के उपरांत आगामी वर्ष में किए जानेवाले कार्यों के बारे में चर्चा की गयी। इस चर्चा में आगामी वर्षभर में पूरे प्रांत में 5000 वृक्ष लगाने, स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरुकता फैलाने, विद्यार्थी विकासार्थ के कार्यों को हर इकाई तक पहुँचाने आदि का लक्ष्य तय किया गया।

इसके बाद जल-संरक्षण, मृदा-संरक्षण, पर्यावरण-सुरक्षा तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा बताया गया कि आनेवाले समय में विद्यार्थी विकासार्थ पर्यावरण-संरक्षण के प्रति अभियान चलाया जायेगा।

समापन-सत्र के बाद प्रांत संगठन मंत्री मधुसूदन जोशी ने कार्यशाला में आए हुए अतिथियों को स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया और सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। ■

फिर हुई अभाविप के संघर्ष की जीत

जल्द शुरू होगी एल. एल.बी. प्रवेश-प्रक्रिया, नहीं घटेंगी सीटें

नयी दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में लटकी एल. एल.बी. दाख़िले की प्रक्रिया को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के संघर्ष की फिर जीत हुई है। विश्वविद्यालय-प्रशासन ने अभाविप की मांगों को मानते हुए एल. एल. बी. की सीटों पर दाख़िला-प्रक्रिया जल्द शुरू किए जाने की बात कही है। साथ ही प्रशासन ने माना कि एल. एल. बी. की सीटों में किसी प्रकार की कटौती भी नहीं की जाएगी।

दरअसल, विश्वविद्यालय-प्रशासन में बीते माह एक नोटिस जारी करते हुए कहा था कि एल. एल. बी. में प्रवेश को लेकर 800 सीटें घटाई जाएँगी, जिसके बाद छात्र संगठन विरोध में उतरे थे। विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष सत्येंद्र अवाना के नेतृत्व में भूख हड़ताल भी की। सत्येंद्र अवाना ने कहा कि यह छात्र-हित का मामला है और प्रशासन को अपनी गलती सुधारनी होगी। उन्होंने कहा कि एक तो वैसे ही सीटों की संख्या काफ़ी कम है, उस पर यदि और भी सीटें कम की जाएँगी, तो छात्र प्रवेश कैसे ले पायेंगे।

छात्रों की मांग थी कि न सिर्फ एल. एल. बी. की सीटों पर दाख़िला-प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए बल्कि सीटें घटाने की कोशिशों पर भी विराम लगाया जाए। इसके पश्चात् डीन छात्र कल्याण प्रो. जे. एम. खुराना ने मांगों पर विचार किए जाने की बात कही थी। साथ ही छात्रों को जूस पिलाकर भूख हड़ताल ख़त्म कराते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया था।

सुरक्षा-जांच पर बवाल, छात्रों ने किया प्रदर्शन

नयी दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस-जैसे विशेष अवसर पर पुलिस सामान्य से ज्यादा गश्त पर रहती है और किसी भी संदेहास्पद स्थिति में जाँच का दायरा और सख़्त कर दिया जाता है। ऐसे में सुरक्षा-जाँच को छात्रों द्वारा अधिकारों का उल्लंघन बताना और फिर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करना किसी भी लिहाज़ से सही नहीं ठहराया जा सकता।

दरअसल, सुरक्षा-कारणों को लेकर चाक-चौबंद पुलिस को सूचना मिली थी कि जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रावास में कुछ संदिग्ध लोग छात्रों से साथ रह रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस का दस्ता विश्वविद्यालय-परिसर में निरीक्षण के लिए पहुँचा और छात्रावास की जाँच की। जिसके बाद जामिया के छात्रों ने दिल्ली पुलिस की अचानक जांच का विरोध किया। छात्रों का कहना था कि यह पुलिस की 'रेड' थी। जबकि पुलिस अधिकारियों का कहना था कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा के मद्देनजर सामान्य जांच हुई।

इसी सुरक्षा जाँच को लेकर गुटों में छात्र इकट्ठे हो गए और पुलिस पर अधिकारों के हनन का आरोप लगाने से नारेबाजी करने लगे। इतना ही नहीं, छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर महताब आलम के कार्यालय के सामने भी प्रदर्शन किया। इस पर जामिया-प्रशासन ने छात्रों को पुलिस की नियमित जांच का हिस्सा बताते हुए मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं माने।

जामिया के छात्र अबूजर का कहना था कि वह चार साल से जामिया में पढ़ रहा है और हॉस्टल में रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस हॉस्टल में बिना अनुमति के जांच करे। यह रेड छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है। उसने कहा कि विश्वविद्यालय में आर्मी के रिटायर्ड गार्ड हैं जो आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा के लिए हमारी जांच कर सकते हैं, लेकिन हमें अलग मानकर इस तरह परेशान करना ठीक नहीं है।

मीडिया के मनोविज्ञान को समझना ज़रूरी : के.जी. सुरेश

'वर्तमान समय में मीडिया की कार्यप्रणाली में काफ़ी बदलाव आया है। परंपरागत ख़बरों से इतर भी कई मुद्दे कभी-कभी बहस का हिस्सा बन जाते हैं। आए दिन हम टी.वी. चैनलों में किसी-न-किसी मुद्दे पर बहस होते देखते रहते हैं। किसी भी बहस में भाग लेने से पहले उस मुद्दे को गहन रूप से जान लेना ज़रूरी है। मुद्दे को जानना ही आजकल काफ़ी नहीं रह गया है, मुद्दे की जानकारी के साथ-साथ विपक्षी इस पर क्या राय रखते हैं, उसकी सोच क्या है, इसे जानना भी अति आवश्यक है। टी.वी. चैनलों पर बहस के दौरान या अख़बारों के लिए साक्षात्कार के दौरान मीडिया सामनेवाले को उलझाने का काफी प्रयास करता है। वर्तमान दौर में यदि चर्चा में टिके रहना है तो मीडिया के मनोविज्ञान को समझना ज़रूरी है।' उक्त बातें भारतीय जनसंचार संस्थान के निदेशक के.जी. सुरेश ने **'मीडिया के स्वरूप और आवश्यकता'** विषय पर अभाविप द्वारा आयोजित मीडिया कार्यशाला में कही। नोएडा स्थित सुदर्शन चैनल के भवन में आयोजित इस दो-दिवसीय कार्यशाला में दिल्ली प्रदेश के 60 से अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यशाला में उद्घाटन से लेकर समापन तक कुल सात सत्र हुए।

द्वितीय सत्र को संबोधित करते हुए भारत नीति प्रतिष्ठान के मानद निदेशक डॉ. राकेश सिन्हा ने राष्ट्रवाद की परिभाषा से लेकर उसके विभिन्न स्वरूप व भारतीय संकल्पना के बारे में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को समझाया। उन्होंने भारतीय सभ्यता को पश्चिमी राष्ट्रों की सभ्यता से अलग और श्रेष्ठ बताते हुए चंद्रगुप्त और सरदार पटेल के तथ्य द्वारा स्थापित राष्ट्र की परिभाषा को समझने और उसकी परंपरा को अग्रसर करने का आह्वान किया।

तृतीय सत्र में व्यावहारिक प्रशिक्षण के बारे में गट चर्चा में प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के बारे में वरिष्ठ पत्रकार ऋषभ सक्सेना, निखिल कुमार तथा अभाविप के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक साकेत बहुगुणा ने बताया। इसी सत्र के दूसरे गट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पैनल चर्चा का व्यावहारिक प्रशिक्षण चैनल के स्टूडियो में कैमरे के सामने दिया गया। इस परिचर्चा में एंकर के रूप में मीनाक्षी श्योराण ने तीन बड़े मुद्दों पर शो रिकार्ड करवाया व बाद में इस पर समीक्षा करते हुए वरिष्ठ पत्रकार रोहित सावल व पत्रकारिता के शिक्षक राकेश योगी ने कार्यकर्ताओं को अच्छी परिचर्चा करने हेतु मार्गदर्शन किया।

इसके बाद चतुर्थ सत्र में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर सामूहिक चर्चा हुई।

पंचम सत्र में **'वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मीडिया का उपयोग'** विषय पर बताते हुए वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने ने कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता है। हर अख़बार, मैगज़ीन या चैनल का एक मिज़ाज़ होता है, उसे समझकर उसके अनुरूप उनसे संवाद स्थापित करना चाहिए। संपर्क और संवाद स्थापित कर, 'न्यूज' पहचानने की कला स्थापित कर व व्यक्तिगत मित्रता के द्वारा पत्रकारों से अपने विचार को लाभ पहुँचाया जा सकता है।

षष्ठ सत्र में कार्यकर्ताओं के मन में आनेवाले विभिन्न प्रश्नों का ज़वाब देते हुए अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री ने कहा कि परिषद् हमेशा से ही राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी विशेष भूमिका अदा करती है।

समापन-सत्र में मुख्य अतिथि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.ब्रजकिशोर कुठियाला ने कार्यकर्ताओं को संवाद की आवश्यकता व गुणों से अवगत कराते हुए मीडिया का सेनापति बनने का आह्वान किया। साथ ही वैकल्पिक मीडिया का अधिकतम उपयोग करते हुए सकारात्मक चर्चा करने पर बल दिया। इस सत्र के विशिष्ट अतिथि सुदर्शन टीवी के चेयरमैन सुरेश चव्हाणके ने सुदर्शन टीवी के उद्भव व विकास पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित कार्यकर्ताओं को मीडिया के क्षेत्र में उद्यमी के रूप में स्थापित होने के गुर सिखाए। अभाविप के राष्ट्रीय मीडिया-संयोजक साकेत बहुगुणा ने दो-दिवसीय कार्यशाला का सारांश सभी के सम्मुख रखा। कार्यशाला की शुरूआत में प्रस्तावना को राष्ट्रीय मीडिया एवं जनसंपर्क-प्रमुख श्रीरंग कुलकर्णी ने रखा और कार्यशाला की भूमिका व महत्त्व पर प्रकाश डाला।

विश्वविद्यालय पत्रिका में 'लाल सलाम', अभाविप ने जताया विरोध

विद्यार्थी परिषद् ने की रोहित वेमुला को शहीद बताने की निन्दा

पुदुच्चेरी। पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका में रोहित वेमूला को शहीद बताने तथा वामपंथी विचार को छात्रों पर थोपे जाने की घटना ने एक विवाद को जन्म दिया। ग़लत तथ्यों को प्रकाशित किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रोष-प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पत्रिका की कुछ प्रतियों का जलाया भी। अभाविप-कार्यकर्ताओं का कहना है पत्रिका 'वीडरस्टैंड' एक विवादित प्रकाशन है, जिसके संदर्भ में विश्वविद्यालय-प्रशासन द्वाना कोई सर्कुलर नहीं जारी किया गया। ऐसे में छात्र-गतिविधियों के प्रकाशन की जगह किसी ख़ास विचारधारा (वामपंथी सोच) के हिसाब से विश्वविद्यालय की पत्रिका नहीं छपनी चाहिए। छात्रों का कहना है कि इस पत्रिका के लिए 3.5 लाख रुपये जो खर्च किए गये, वे भी छात्र कल्याण कोष के थे।

पत्रिका के तथ्यों को लेकर अभाविप ने छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीन) के कार्यालय के समक्ष भी प्रदर्शन किया, पत्रिका की प्रतियाँ जलाईं और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूछा गया कि पत्रिका के आवरण-पृष्ठ पर एक फीलिस्तीनी महिला का चित्र है जिसने इजराइल द्वारा छोड़े गए आँसू गैस के गोले से गुलदस्ता तैयार किया। आख़िर यहूदियों ने मुस्लिमों पर अत्याचार किया, ऐसा संदेश क्यों दिया जा रहा है। उससे भी बड़ा सवाल यह कि इसका पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय के छात्रों के विकास से क्या संबंध है? क्या इस प्रकार के तथ्यों से कैंपस में यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा करना मकसद है?

इतना ही नहीं, ख़ुदकुशी करनेवाले रोहित वेमुला को शहीद दिखाने की कोशिश किस प्रकार से विश्वविद्यालय या छात्र-हित में है? क्या विश्वविद्यालय-प्रशासन और वामपंथी संगठन (एसएफआई) छात्रों को ख़ुदकुशी के लिए प्रेरित करना कहता है? विश्वविद्यालय की वार्षिक पत्रिका के बैक कवर पर 'लाल सलाम' और 'जय भीम' का संदेश क्यों? यदि कोई संदेश देना है कि 'जय हिंद' का होना चाहिए न कि विचार विशेष का। साथ ही 'संघवाद से आज़ादी' और 'मनुवाद से आज़ादी'-जैसे नारों

से पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय किस प्रकार छात्रों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करेगा।

अभाविप ने स्पष्ट किया कि हमें अपने देश के संविधान में पूरी आस्था है और 'जय भीम' या कोई नारा लगाने से हमारी देशभक्ति आहत भी नहीं होगी। लेकिन 'लाल सलाम'-जैसे शब्दों का विरोध हमेशा होगा। छात्र उन शब्दों का समर्थन नहीं करेगा जिसके उद्घोष के साथ हमारे जवानों की हत्या की जाती हो। 'लाल सलाम' इस देश में या तो नक्सली बोलते हैं या फिर माओवादी। हाँ, कम्युनिस्ट भी इसे अपना नारा मानते हैं तो वे बोलें, मगर विश्वविद्यालय-पत्रिका में यह नहीं प्रकाशित किया जाना चाहिये; क्योंकि पत्रिका किसी वामपंथी संगठन के चंदे से नहीं, बल्कि छात्रों की सुविधाओं के लिए आनेवाले पैसों से छपती है।

विद्यार्थी परिषद् के विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सफ़ाई देते हुए कहा कि पत्रिका का लोकार्पण करनेवाले कुलपति को पत्रिका के विषय सूची (कंटेंट) की जानकारी नहीं थी। साथ ही आनन-फानन में प्रशासन ने छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीन) को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। इस बीच एसएफआई कार्यकर्ताओं ने पत्रिका की कॉपी प्राप्त कर ली और उसे ऑनलाइन साइट 'अमेजन डॉट कॉम' पर बेचने के लिए लगा दी। ऐसे में यह तय है कि पत्रिका के प्रकाशन से लेकर उसके मुद्रण तक में प्रशासनिक अधिकारियों और वामपंथी संगठन के बीच साँठगाँठ है। ■

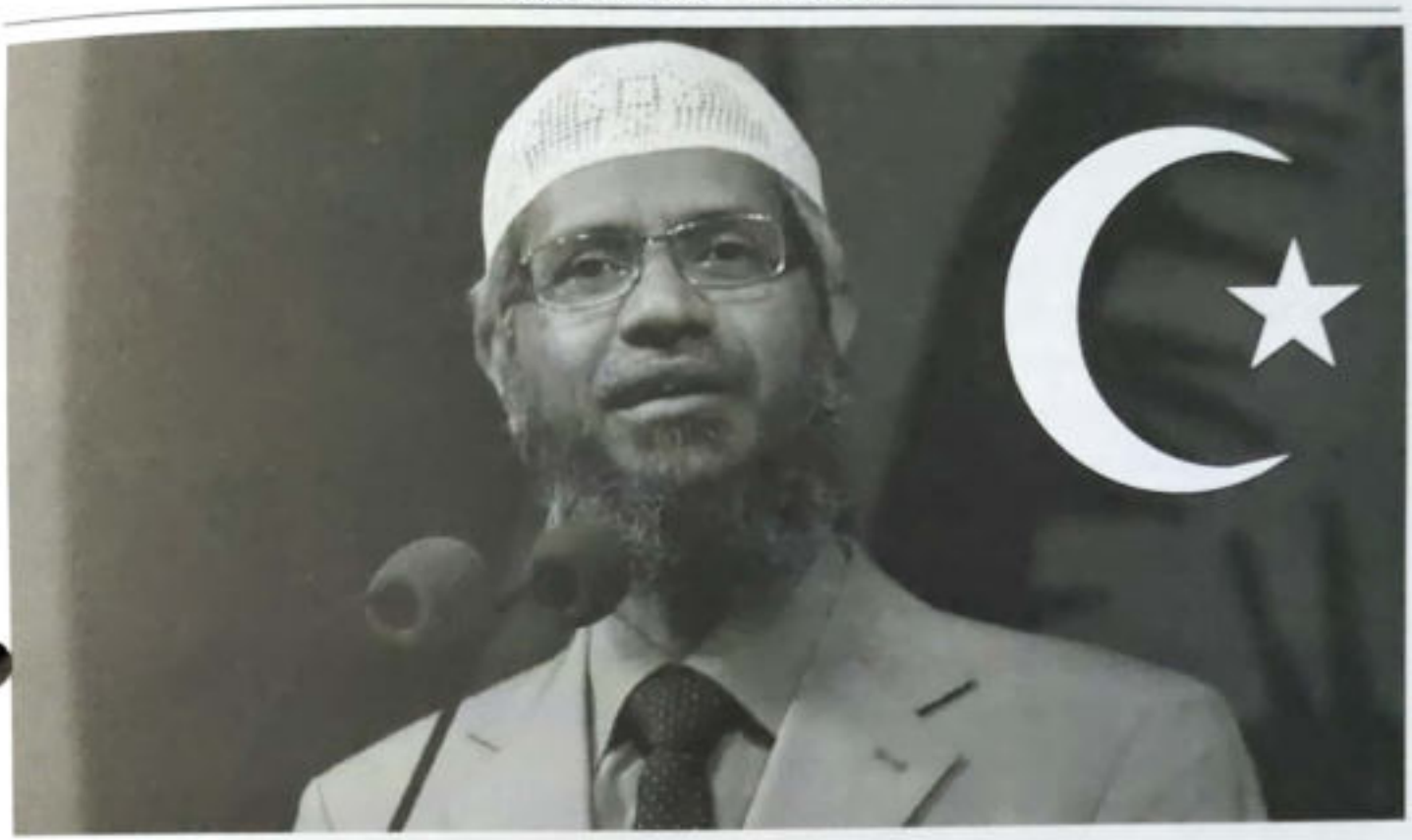

ज़ाकिर नाईक : इस्लाम का नया आतंक

■ राकेश यादव

पिछले कुछ दिनों में हुए आतंकी हमलों ने संपूर्ण मानव जाति को आतंकी भय के साये में खड़ा कर दिया। इससे भी ज्यादा एक धर्म-विशेष की वास्तविकता को उजागर किया और ढाका से मदीना तक, पेरिस से इस्तांबुल तक, बगदाद से लेकर पाकिस्तान तक सभी हमलों में 'अल्लाह हो अकबर' के नारों ने इस्लामिक आतंक का भयावह परिचय दिया।

इस्लाम के नाम पर किए गए इन हमलों का मुस्लिम आवाम द्वारा एकजुट होकर विरोध किया जाना चाहिए जबकि इसके विपरीत कुछ धार्मिक नेता और उलेमा इसको न्यायिक करार देने की पैरवी करते नज़र आये। ये धार्मिक गुरु आतंकियों को मजहब से दायरे से बाहर निकालने के लिए सदैव उपस्थित होते हैं, परन्तु मुस्लिम धर्म की आर्थिक, सामाजिक हालातों के साथ मुस्लिम महिलाओं की दयनीय हालातों के संदर्भ में इन गुरुओं की चुप्पी उनकी धार्मिक निष्ठा पर सवाल खड़े करती है।

इस्लामिक धार्मिक गुरु ज़ाकिर नाईक की बांग्लादेश के आतंकी हमलावारों के साथ संबंधों पर संपूर्ण मीडिया व वैचारिक मंचों पर एक नया विवाद सामने आया। कुछ कट्टरपंथी लोग ज़ाकिर को 'धर्मगुरु' की उपाधि ने नवाज़ रहे थे तो दूसरी ओर आतंकियों के ज़ाकिर द्वारा प्रेरित होने के कारण वे संदेह के घेरे में थे। यह सम्पूर्ण घटना एक ऐसे धार्मिक गुरु के सन्दर्भ में है जिसके धर्म में धर्मिक मान्यताएँ वर्तमान परिदृश्य में भी रूढ़िवादी इस्लामिक रीतियों से जकड़ी हुई हैं और महिलाएँ आज भी बुर्के से बाहर नही आ पाई हैं। जहाँ खतना, चार शादी, कथित तलाक-जैसी कुरीतियाँ प्रचलित हैं। ऐसे में किसी भी धर्म के संरक्षणकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठना लाज़मी है।

ज़ाकिर डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद 2006 में पीस चैनल के जरिये व्यापार में आया और एजुकेशनल चैनल की आड़ में सबसे बड़ा इस्लामिक चैनल बना दिया। ज़ाकिर के धार्मिक उद्देश्य पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या मुंबई-जैसे शहर में बैठकर पाँचसितारा होटलों में धार्मिक उपदेश के कार्यक्रम प्रसारित करना सच्ची धार्मिक हिफ़ाजत है? या एक

डॉक्टरी पेशे से मानवीय भाव से आवाम की सेवा करना एक सच्चे धर्मगुरु की निशानी है।

ज़ाकिर नाईक ने मानवीय सेवा के पेशे को छोड़कर धार्मिक गुरु बनने का निर्णय लिया और समाज उत्थान की बात न करके उलटे मुस्लिम महिलाओं के शोषण को आमजन में बढ़ावा देने को प्रेरित करते हैं। जिस धर्म में महिला-साक्षरता 53.7 प्रतिशत है, 7 से 16 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल जानेवाली लड़कियों की दर केवल 3.11 प्रतिशत है, जिस धर्म में केवल एक चौथाई महिलाएँ ही रोज़गार कर पाती हैं, जहाँ 11 प्रतिशत बच्चे ही सैकेंडरी स्तर तक जा पाते हैं, कुल आबादी के 30 प्रतिशत स्कूल या मदरसों में नामांकन भी नहीं कर पाते, ऐसे धर्म में नाईक द्वारा महिलाओं को केवल गुलाम करार देना मूर्खतापूर्ण है।

ज़ाकिर नाईक के महिला से संबंधित अपने बयानों में अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय अनेक बार दिया है। अपने चैनल के माध्यम से आत्मघाती हमलों को बहुत बार उचित ठहराया। जाकिर नाईक के अपने ही धर्म की आधी आबादी के लिए जो विचार हैं वे धर्म से अधिक महिला-शोषण को बढ़ावा देते हैं। और अपने धार्मिक विचारों में कुरआन व हदीस के आदेशों का सहारा लेकर खतने-जैसे अमानवीय कृत्य को न्यायोचित ठहराते हैं।

धार्मिक समूहों की अपनी-अपनी मान्यताएँ हो सकती हैं, परन्तु ये धार्मिकता समाज व धर्म के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की चिन्ता से बढ़कर नहीं हो सकती। जहाँ तक ज़ाकिर के आतंकी संबधों की बात है और भारतीय सरकार पर उसे निशाना बनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तब यह जानना ज़रूरी है कि 2010 में ब्रिटेन व कनाडा में भी आतंकी गतिविधियों के साथ संबंधों के कारण ज़ाकिर पर प्रतिबंध लगाया गया था। ज़ाकिर के आतंकी कनेक्शन बांग्लादेश से लेकर 26/11 तक सबके समक्ष हैं। मुम्बई हमलों की जाँच में हेडली के मुम्बई-प्रवास के दौरान नाईक के साथ रहने के साक्ष्य मिले थे और इसी के चलते उन्हें 2012 में मुम्बई में पीस कॉन्फ्रेंस की अनुमति नहीं दी गयी। दुनियाभर में इस्लामिक आतंकवाद के मसीहा ओसामा बिन लादेन को भी जाकिर ने आतंकी मानने से मना कर दिया था।

जून, 2016 में ढाका में होली आर्टिसन बेकरी पर हुए हमले में 28 लोग मारे गये। हमलावरों में निबांस इस्लाम व रोहान इम्तियाज़ ने कुछ दिन पूर्व ही ज़ाकिर के भाषणों को अपने फेसबुक पर शेयर किया। बांग्लादेश-हमले के आतंकी, नाइक के चरमपंथी भाषणों से प्रेरित थे। हैदराबाद में गिरफ़्तार किए गए आईएसआईएस मड्यूल मुखिया मोहम्मद इब्राहिम यज़दानी ने नाईक के आईएसआईएस के साथ संबधों को भी उजागर कर दिया क्योंकि यजदानी नाईक का सक्रिय सहयोगी रह चुका है। आतंकी हमलों में शिक्षित परिवारों के बच्चे जिससे प्रेरित होकर इस्लामिक आतंकवाद के लिए हथियार उठा ले रहें हैं, उस व्यक्ति को आतंकी प्रेरक ही कहा जा सकता है। ऐसे धार्मिक गुरुओं के कारण ही मुस्लिम युवा उस कट्टर विचारधारा के समर्थन में आ रहे हैं और ढाका, पेरिस, इस्तांबुल की घटनाओं को अंज़ाम दे रहे हैं।

विचारणीय तथ्य यह है कि ज़ाकिर नाईक के चैनल का दर्शक-वर्ग पढ़ा-लिखा व आर्थिक रूप से समर्थ है और उससे प्रेरणा पानेवाले आतंकी भी उसी वर्ग-समूह से निकल रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या ज़ाकिर पीस फाउंडेशन व चैनल की आड़ में शिक्षित इस्लामिक आतंकी निर्माण कर रहा है? ■

प्रिय मित्रो !

शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का अगस्त 2016 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों तथा ख़बरों का संकलन किया गया है। आशा है, यह अंक आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें :

संपादक, 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
'छात्रशक्ति भवन',
26 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली-110002
फोन : 011-23216298
Visit us at : www.abvp.org

chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/chhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

परिषद्-संघर्ष

लखनऊ, उत्तरप्रदेश में विधानसभा-घेराव के दौरान पुलिस से भिड़ते और धरने पर बैठे कार्यकर्ता

विराट् छात्र-प्रदर्शन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

छात्र-प्रदर्शन के बाद धरने पर
बैठे अभाविप के महामंत्री एवम् अन्य

एमनेस्टी इंटरनेशनल के विरोध में प्रदर्शन
बंगलुरू

महिला-उत्पीड़न के विरोध में छात्राओं का प्रदर्शन
लखनऊ (उत्तरप्रदेश)

RNI 32464/78

स्वच्छता से समृद्धि

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

स्वच्छ मध्यप्रदेश

- मध्यप्रदेश में 54 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों में शौचालय बने।
- 2400 से ज्यादा ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त।
- सभी स्कूलों एवं आंगनवाड़ी में शौचालय निर्माण प्रगति पर।
- दो अक्टूबर 2019 तक सभी घरों में होंगे शौचालय।
- इंदौर जिला देश में स्वच्छता में दूसरे नम्बर पर।

स्वच्छ मध्यप्रदेश सुरक्षित परिवेश

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी